



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2016/फाल्गुन 12, 1937

No. 66]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2016/PHALGUNA 12, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2016

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : चीनी जनवादी गणराज्य मूल की अथवा वहां से निर्यातित “कोऊमेरीन” के आयातों पर पाटन-रोधी निर्णायक समीक्षा (एस एस आर) जांच ।

फा. सं. 15/26/2014-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियम भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 10 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या 14/17/2009-डीजीएडी द्वारा चीन जनवादी गणराज्य (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) मूल की अथवा वहां से निर्यातित “कोऊमेरीन” (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच की शुरुआत की थी । इसका प्रारंभिक निर्णय प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था जिसमें दिनांक 29 जनवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/17/2009-डीजीएडी द्वारा चीन जनवादी गणराज्य मूल की अथवा वहां से निर्यातित “संबद्ध वस्तुओं” के आयातों पर अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2010 की अधिसूचना संख्या 38/2010-सीमा शुल्क द्वारा चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित “संबद्ध वस्तुओं” के आयातों पर अनन्तिम शुल्क लगाया गया था । प्राधिकारी के अंतिम निर्णय की अधिसूचना, दिनांक 7 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/17/2009-डीजीएडी में प्रकाशित की गई थी । केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2010 की

अधिसूचना संख्या 82/2010-सीमा शुल्क द्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “संबद्ध वस्तुओं” के आयातों पर निश्चित पाटन-रोधी शुल्क लगाए गए थे।

3. फ्रेग्रेस एंड फ्लेवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सीईएसटीएटी के समक्ष एक अपील दायर करके पाटन-रोधी शुल्क लागू करने को चुनौती दी थी। माननीय सीईएसटीएटी ने दिनांक 17 जून, 2011 के आदेश द्वारा अंतिम निर्णय और सीमा शुल्क विभाग की दिनांक 20 अगस्त, 2010 की अधिसूचना को खारिज कर दिया था तथा मामले को वापिस निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस निर्देश सहित लौटा दिया था कि 6 महीनों के भीतर याचिकादाता को उचित सुनवाई का मौका दिया जाए तथा इस संबंध में नया निर्णय लिया जाए। प्राधिकारी ने दिनांक 23 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना संख्या 14/17/2009-डीजीएडी द्वारा नए निर्णय को प्रकाशित किया था तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा 8 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा शुल्क द्वारा पाटन-रोधी शुल्क लागू करने की संबद्ध अधिसूचना जारी की गई थी।

4. मेसर्स एटलस फाईन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड जिसे 23 अक्टूबर, 2015 से मेसर्स एम्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड ने अधिग्रहीत कर लिया है और जिसे अब मेसर्स एम्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड (जिसे आगे याचिकादाता कहा गया है) के नाम से जाना जाता है, ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष पर्याप्त प्रमाणों सहित विधिवत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने यह आरोप लगाया है कि चीन जनवादी गणराज्य मूल की अथवा वहां से निर्यातित “संबद्ध वस्तुओं” के आयातों के निरंतर पाटन होने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने तथा उससे घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है तथा उनसे अनुरोध किया है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित “संबद्ध वस्तुओं” के आयातों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों की पुनरीक्षा की जाए, उनको निरंतर जारी रखा जाए तथा उनको बढ़ाया जाए। तदनुसार प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (क) 5 के अनुसार अधिसूचना सं.15/26/2014-डीजीएडी के तहत निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की है, ताकि चीन जनवादी गणराज्य मूल (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) की अथवा वहां से निर्यातित “संबद्ध वस्तुओं” के संबंध में लागू किए गए शुल्कों को निरंतर जारी रखे जाने की समीक्षा की जा सके तथा इसकी जांच की जा सके कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने तथा उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

ख. क्रिया-विधि

5. प्राधिकारी ने इस जांच के संबंध में निम्नोक्त क्रिया-विधि का अनुसरण किया है :-

- (1) प्राधिकारी ने उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 16 मार्च, 2015 की जांच की शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ-साथ घरेलू उत्पादकों को भी प्रेषित की थी। ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें तथा इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपने लिखित विचारों से प्राधिकारी को अवगत कराएं। निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची के साथ संबद्ध देश के दूतावास को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थीं कि वे संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को यह परामर्श दें कि वे इस संबंध में प्रश्नावली के अपने उत्तर निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्राधिकारी को भेज दें।
- (2) नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार याचिकादाता की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के अगोपनीय वृत्तान्त की प्रति संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, उत्पादकों और दूतावास को उपलब्ध कराई गई थी।
- (3) प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करने संबंधी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रेषित की गई थी और उन्हें नियमावली के अनुसार इस संबंध में जारी किए गए पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया गया था :-

टिआंजिन सिटी नंबर 3, केमिकल रिजेंट फैक्टरी ज्यूआंगजिक्सिआंग डोंगली, जिला-टिआंजिन-300 240.	चांगझाऊ नंबर 2 केमिकल प्लांट 16, चांगकी रोड, किशुआन, चांगझाऊ सिटी जिआंगसू- 213 003.
ननजिंग हुआफा केमिकल कंपनी लिमिटेड, मेशान, झोघुआमेनवाई जिआंगनिंग काउंटी नानजिंग सिटी, जिआंगशू-210 039	डोऊमेन काउंटी बेशिफा केमिकल फैक्टरी कंपनी लिमिटेड, डोऊमेन टाउन, डोऊमेन काउंटी झुहाई सिटी, गुआंगडोंग-519

- (4) तथापि, संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं अथावा कोई निवेदन किए हैं।
- (5) बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिपादन (एमईटी) की प्रश्नावली चीन जनवादी गणराज्य के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी को संबद्ध सूचना प्रस्तुत कर दें। जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य पर विधिवत् समायोजन करने के बाद ही भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर विचार किया गया था, जिसके बारे में प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को सूचित किया था कि उनका यथा संशोधित पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और पैरा 8 के आलोक में आवेदकों के दावों की जांच करने का प्रस्ताव है। इसलिए चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों/उत्पादकों से यह अनुरोध किया गया था कि वे इस आशय की आवश्यक सूचना/प्रमाण प्रस्तुत करें कि क्या उन्हें चीन जनवादी गणराज्य में सहयोगी उत्पादक/निर्यातकों के लिए स्वीकृत किए जाने वाले बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण के बारे में विचार किया जा सकता है। तथापि, चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने, चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिपादन (एमईटी) को खंडन करने के लिए प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- (6) नियमावली के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों को आयतक की प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :-

भारत इंडस्ट्रियल कोर्पोरेशन, 341/35, पहला क्रास, दयानंद नगर, श्रीरामपुरम, बंगलौर-560 021.	फ्लोरल फ्रेग प्राईवेट लिमिटेड, बोनोफाईड लेन, प्रथम तल, कोलकाता-700 001.
ईस्टर्न एजेंसीज, 301, मंगल सिमरन, 28वां रोड, ऑफ टर्नर रोड, बान्द्रा (पश्चिम), मुंबई-400 050.	पीबीएस फ्रेगरेंसिज प्राईवेट लिमिटेड, 25 ए हिमालय हाऊस, 79 पलटन रोड, मुंबई-400 001.
तुषार इंटरप्राइजिस, 14/ए, मसकती मार्किट, मोती महल होटल के पास, कालूपुर, अहमदाबाद- 380 002.	कर्नाटक सोप्स एंड डेटरजेंट्स लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 5531, बंगलौर- पुणे हाईवे, बंगलौर 560 055
शालीमार अगरवत्ती, पोस्ट बॉक्स नंबर 2114, नंबर 32 और 33, तीसरा क्रोस, श्रीरामपुरम, बंगलौर-560 021.	वासु अगरवत्ती, नंबर 2203, पोस्ट बॉक्स नंबर 390, न्यू सैय्याजी राव रोड, मैसूर, कर्नाटक
साची ऐरोमेटिक्स, वाई-4, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-2, नई दिल्ली-110 020.	गुप्ता एंड कंपनी, 68, सिंधिया हाऊस, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001.
जीसी इंटरनेशनल लिमिटेड, 3 बी-57, ब्लू मून इस्टेट, भूतल, मोन्जिनिस लेन, ऑफ अंधेरी लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई.	अल्फा केमिका, मोहिद हाइट्स यूनिट नंबर 5, चौथा तल, लोखानवाला, आरटीओ रोड, ऑफ फोर बंगलाज, वर्सोवा टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई.
मौर्य ग्लोबल प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर ए-42, स्ट्रीट नंबर 2, एम.आई.डी.सी. अंधेरी (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र-400 093.	दीपक केमिकल्स ग्रुप, 2207, फेज-4, जीआईडीसी, वाट्वा, अहमदाबाद-382 245.
भगत इम्पेक्स, सी-33 और 34, सेक्टर-7, नोएडा- 201 301 (उत्तर प्रदेश).	लौरिस लैब्स, 308, अंजलि, बी विंग, अम्बिका नगर सॉक, एम.जी.रोड, दोम्बीवली (पश्चिम)-4 21 202.
एनएस केमिकल्स, 601-611, देवाव्रत, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई- 400	नागपुर केमिकल्स, डब्ल्यू-36 एमआईसीडी, हिंगवा रोड, नागपुर- 440 016
फ्रेगरेंसिज एंड फ्लेवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नवीनचंद्र रंछोदास शाह हाल, 2-बी, कोर्ट चेम्बर्स, दूसरा तल, 34, सर विठ्ठलदास ठाकरे मार्ग, मुंबई-400 020.	

- (7) किसी भी आयातक, प्रयोक्ता अथवा एसोसिएशन ने आयातक की प्रश्नावलियों के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- (8) मौखिक सुनवाई में हालांकि फ्रेगरेंसिज एंड फ्लेवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन उसने सुनवाई के बाद एक पत्र प्रस्तुत करके कुछ निवेदन किए थे। इस एसोसिएशन द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की गई है और जांच के दौरान किए गए अन्य निवेदनों के साथ उनका निदान किया गया है।
- (9) ऐसे निर्यातकों, उत्पादकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने प्राधिकारी को न तो कोई उत्तर प्रस्तुत किया है और न ही इस जांच से संबद्ध कोई सूचना प्रदान की है, असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- (10) आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने के चरण में घरेलू उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय सूचना सेवा (आईबीआईएस), मुंबई से प्राप्त आंकड़ों पर विश्वास करते हुए याचिका दायर की है। उसने चीन सीमा शुल्क से आयात के आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं और उनकी तुलना, आईबीआईएस के साथ करके, यह दावा किया है कि चीन के सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के दौरान चीन से निर्यातों की मात्रा, आईबीआईएस द्वारा सूचित आंकड़ों से काफी अधिक है। जो कि भारतीय सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों पर आधारित हैं। उसके बाद घरेलू उद्योग ने चीन के सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त कारोबार-वार आयात के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं तथा प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक विश्लेषण करने के लिए उन पर विश्वास करें क्योंकि जांच अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के सूचित किए गए निर्यात, आईबीआईएस और डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों से काफी अधिक हैं।
- (11) यह आवेदन पत्र आईबीआईएस आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा जांच की शुरुआत करने के लिए प्रथम दृष्टया प्रमाण पर विश्वास किया गया है। जांच शुरुआत करने के बाद महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त किए गए कारोबार-वार आयात के आंकड़े प्राप्त किए गए थे। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए आयात के आंकड़ों की तुलना की गई थी और यह नोट किया जाता है कि चीन के सीमा शुल्क विभाग द्वारा सूचित आयातों की मात्रा, डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में निर्दिष्ट आयातों से काफी अधिक है। तथापि, चूंकि चीन के सीमा शुल्क विभाग द्वारा सूचित आंकड़ों में समुद्री विक्रियों के अधिक कारोबार की मनाही नहीं की जा सकती है, इसलिए प्राधिकारी ने इस निर्णय में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- (12) भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुकूलतम लागत और निर्माण की लागत तथा बिक्री की लागत का आकलन, सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएपीपी) के आधार पर किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटन-रोधी शुल्क, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा। पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार प्राधिकारी द्वारा एनआईपी निर्धारित की गई है।
- (13) वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल, 2013 से सितंबर, 2014 तक है। तथापि, क्षति का विश्लेषण करने की अवधि में अप्रैल 2010-मार्च, 2011, अप्रैल, 2011-मार्च, 2012, अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तथा जांच की अवधि (पीओआई) भी शामिल है।
- (14) पाटन-रोधी शुल्क नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 6 नवंबर, 2015 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया था। इस मौखिक सुनवाई में केवल घरेलू उद्योग ने अपने कानूनी सलाहकार के साथ अपने विचार प्रस्तुत किए थे तथा उनसे अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करें।
- (15) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना तथा आंकड़ों की जितना आवश्यक समझा गया है, मौके पर जांच की गई है।
- (16) इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की, प्राधिकारी द्वारा जितना प्रासंगिक समझा गया है, उतनी जांच की गई है तथा उनका निदान इस जांच में किया गया है।
- (17) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की प्राधिकारी द्वारा उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक समझा है, संतुष्ट होने पर

गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है तथा विचारित उसे गोपनीय सूचना माना है और उसे प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के पर्याप्त अगोपनीय वृत्तान्त प्रदान करें।

- (18) जहां कहीं भी यदि किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना का अभिगमन करने अथवा उसे अन्यथा प्रदान नहीं करने से मनाही की है अथवा जांच में विशेष रूप से अडचन पैदा की है, प्राधिकारी ने “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर उसे इस अंतिम निर्णय में अनिवार्य तथ्यों के रूप में रिकार्ड किया है तथा ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है।
- (19) इस प्रकटन विवरण में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की परिचायक है और प्राधिकारी ने इसे नियमावली के अंतर्गत गोपनीय माना है।
- (20) इस निर्णय के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर = 60.76 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और “समान वस्तु”

6. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार का “कोऊमेरीन” (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) है। इस उत्पाद को शुल्क टेरिफ अधिनियम के अध्याय 29 (आर्गेनिक केमिकल) के अंतर्गत सीमा शुल्क के उप-शीर्ष संख्या 2932.21.00 अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से मौजूदा जांच पर बाध्यकारी नहीं है। चूंकि मौजूदा जांच निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का कार्य-क्षेत्र वही रहेगा जो कि मूल जांच में था। मूल जांच के अंतिम निर्णय में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था :-

“मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार की कोऊमेरीन (जिसे आगे “संबद्ध वस्तुएं” कहा गया है) है। कोऊमेरीन (रसायनिक फार्मूला सी 9 एच 602) रसायनों के लेक्टोन समूह से संबंधित है। यह एक एरोमा रसायन है, जो कि सफेद क्रिस्टल, फ्लेक अथवा पाउडर के रूप में हो सकता है। इसकी गुण विशेषता नए माउन हे की गंध का होता है और कुछ खट्टे मीठे स्वाद का होता है जो कि वेनीला के समान होता है। कोऊमेरीन का उपयोग सुगंध मिश्रण तैयार करने और ऐसे सुगंधित मिश्रणों का साबुन, डिटरजेंट्स, प्रसाधन सामग्री, अगरबत्तियों और अति सुगंधित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। यह अत्यंत सुगंध सृजित करता है और अन्य अनेक घरेलू और औद्योगिक उत्पादों में से दुर्गंध को छिपा देता है। कोऊमेरीन जो कि मुख्यतया टोंका फलियों से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद था, अब सिंथेटिक रूप से निर्मित किया जाता है। इसे दो संक्षिप्त प्रक्रियाओं से प्राप्त किया जाता है, अर्थात् (1) प्रारंभ में सेलिकेलिडिहाईड प्राप्त करने से ले कर बाद में पर्किन प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए और (2) प्रारंभ में ओर्थो-क्रिसोल जिसे रेसचिग पद्धति कहा जाता है, जिसमें ओर्थो-क्रिसोल से सेलिकेलिडिहाईड से निर्मित करने से ले कर बाद में कोऊमेरीन परिवर्तित किया जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में सेलिकेलिडिहाईड और एसेटिक एसिड, सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में उत्प्रेरक के रूप में रिएक्ट करता है और अपरिष्कृत कोऊमेरीन को आसवन से एसेटिक एसिड से पृथक किया जाता है। अपरिष्कृत कोऊमेरीन को आगे अनेक आसवन से और परिशुद्ध किया जाता है और उसके बाद उसे मेथेनाल में क्रिस्टलाईज्ड किया जाता है। क्रिस्टलाईज्ड उत्पाद को अभिकेन्द्रण से पृथक किया जाता है और सुखाया जाता है। कोऊमेरीन की मुख्य वास्तविक विनिर्देशन उसकी परिशुद्धता है, जिसके लिए उसका मेल्टिंग प्वाइंट संकेतक होता है”।

7. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जांच की कार्रवाई के किसी भी चरण में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई निवेदन नहीं किया है। चूंकि यह निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए प्राधिकारी वर्तमान समीक्षा जांच के लिए मूल जांच के अंतिम निर्णयों में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद पर विचार करते हैं।

8. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में उल्लिखित व्यवस्था निम्नानुसार है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं ।

9. याचिकादाता ने यह दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित और चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं उनके भौतिक और रासायनिक लक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों जैसी विशेषताओं, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से समान वस्तुएं हैं। दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं का उपयोग, उनके पारस्परिक प्रतिस्थापन के रूप में कर रहे हैं।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में कोई तर्क नहीं दिया है। इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुएं, संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं।

घ. घरेलू उद्योग का कार्य-क्षेत्र और आधार

निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

11. निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और आधार के संबंध में कोई निवेदन नहीं किया गया है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

12. घरेलू उद्योग के कार्य-क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) मेसर्ज एटलस फाईन केमिकल प्राईवेट लिमिटेड, जो कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का एक मात्र उत्पादक है, द्वारा याचिका दायर की गई है। तथापि, मेसर्ज एटलस फाईन केमिकल प्राईवेट लिमिटेड को उससे संबद्ध कंपनी, मेसर्ज एम्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा 23 अक्टूबर से अधिग्रहीत कर लिया गया है। मेसर्ज एटलस फाईन केमिकल प्राईवेट लिमिटेड की समस्त प्ररिसम्पतियां और देयताएं, अब अन्तरिती कंपनी नामतः मेसर्ज एम्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड को अंतरित हो गई हैं।
- (2) समामेलन होने से पहले और बाद में दोनों कंपनियों के प्रवर्तक वही हैं। व्यवसायिक प्रचालनों के संबंध में एटलस कोऊमेरीन की उत्पादक थी, जबकि समामेलन से पहले एम्स इम्पेक्स वेनेलीन की उत्पादक थी। समामेलन के बाद एटलस फाईन केमिकल्स को एम्स इम्पेक्स में समामेलित कर दिया गया। अब एम्स इम्पेक्स कोऊमेरीन और वेनेलीन दोनों की उत्पादक है।
- (3) प्रबंधन ने इस तथ्य को ध्यान में रख कर समामेलन करने का निर्णय लिया था कि क्रियाकलापों और प्रचालनों को एक ही कंपनी में मिलाना लाभप्रद होगा ताकि आपूर्ति की श्रृंखला और संभारतंत्रीय समामेलन, बड़े पैमाने पर प्रचालनों के लाभ, विभिन्न निर्धारित लागत में बचत आदि जैसे सहक्रियाशील लाभ प्राप्त किए जा सकें। व्यवसाय के समेकन के फलस्वरूप लागत में बचत होगी तथा राजस्व और मार्जिन बढ़ेगा। समान प्रचालन मंच एक ऐसा अवसर प्रदान करेगा जिससे संयुक्त परिसम्पतियों का लाभ प्राप्त होगा तथा एक सुदृढ़ सुस्थिर व्यवसाय बनेगा।
- (4) जांच अवधि के दौरान न एटलस फाईन केमिकल प्राईवेट लिमिटेड और न ही एम्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड ने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है अथवा नियम 2 (ख) के अनुसार वे चीन में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत के भीतर विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा प्रयोक्ता से संबंधित हैं।
- (5) भारत में कोऊमेरीन का कोई अन्य ज्ञात उत्पादक नहीं है और इसलिए याचिकादाता का उत्पादन, भारतीय उत्पादन का 100 % बनता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटन वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है”।

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत जांच में प्राधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि -

“प्राधिकारी का यह मानना है कि मेसर्ज एटलस फाईन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, भारत में समान वस्तु की एक मात्र उत्पादक है और यह पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार में “घरेलू उद्योग” बनती है। प्राधिकारी का आगे यह भी मानना है कि आवेदक पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) नियम 5 (3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है”।

15. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि याचिकादाता मेसर्ज एटलस फाईन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड है। तथापि, जांच शुरू करने के बाद की गई जांच में याचिकादाता की पहचान में बदलाव हो गया है। मेसर्ज एटलस फाईन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड को उससे संबंधित कंपनी एम्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड में समामेलित कर दिया गया है। प्राधिकारी ने जांच की है और यह पाया है कि स्वामित्व, परिसम्पत्तियों और देयताओं आदि के रूप में समामलेन हो जाने के बाद भी याचिकादाता की अवस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए प्राधिकारी की ऐसी अवधारणा है कि मेसर्ज एटलस फाईन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड जो कि अब मेसर्ज एम्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात है, विचाराधीन उत्पाद का एक घरेलू उद्योग है।

ड. अन्य मुद्दे**उत्पादकों/निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन**

16. इस संबंध में किसी भी उत्पादक/निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई निवेदन नहीं किया गया है। तथापि, मौखिक सुनवाई के बाद फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर्स एसोसिएशन ने जिसने सूचना देने के बाद भी मौखिक सुनवाई में भाग नहीं लिया था, निम्नलिखित निवेदन किए हैं :

- (क) पाटन-रोधी शुल्क लागू किए जाने से इत्रसाजी सम्मिश्रण, प्रसाधन सामग्री, अगरबत्ती (सुगंधित वस्तुओं) आदि के उत्पादन की लागत बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त उत्पादन की लागत बढ़ने से उनके निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह विवेकपूर्ण होगा कि हमारे उद्योग के लिए स्वस्थ और प्रतिस्पर्द्धी वातावरण बनाया जाए और उसका अनुरक्षण किया जाए जिससे कि वह विश्वव्यापी बाजारों में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा कर सके।
- (ख) पाटन-रोधी शुल्क लागू करने का प्रस्तावित ढांचा अनुचित रूप से अत्यधिक बड़ा है। यह न्यायिक, उचित और न्यूनतम होना चाहिए।
- (ग) चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से कोऊमेरिन के आयातों पर मौजूदा स्वरूप में पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के प्रस्ताव से उत्पादक-संघ के गठन को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त चीन के उत्पादों और घरेलू उत्पादों की कीमतों के बीच असमान्य अंतर होने का अभिप्राय एकाधिकारों और प्रतिबंधित व्यापारिक पद्धति का उल्लंघन करना होगा।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

17. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) याचिकादाता ने चीन के सीमा शुल्क विभाग के साथ-साथ आईबीआईएस के कारोबार-वार आंकड़े प्राप्त किए हैं। इनके साथ ही याचिकादाता ने डीजीसीआईएंडएस से भी कारोबार-वार आयात के आंकड़े प्राप्त किए हैं। चीन के सीमा शुल्क विभाग और आईबीआईएस से प्राप्त किए गए आंकड़ों की तुलना, डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए आंकड़ों के साथ करने से यह पाया गया है कि डीजीसीआईएंडएस के

आंकड़ों में निर्दिष्ट आयात की मात्रा, चीन के शुल्क विभाग द्वारा सूचित आयातों की मात्रा से बहुत कम हैं। इसके अतिरिक्त आईबीआईएस के आंकड़ों में सूचित मात्रा, डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में निर्दिष्ट मात्रा से काफी कम है।

- (2) डीजीसीआईएंडएस के कारोबार-वार आंकड़ों में निर्दिष्ट आयात कीमत, चीन के सीमा शुल्क विभाग की कीमतों से काफी अधिक हैं। इसके अतिरिक्त आईबीआईएस के आंकड़ों में निर्दिष्ट कीमत, डीजीसीआईएंडएस के कारोबार-वार आंकड़ों में निर्दिष्ट आयात कीमत से काफी अधिक है।
- (3) निदेशालय की ऐसी स्थापित स्थिति है कि निदेशालय ऐसे आंकड़ों पर विचार करेगा जो कि अत्यधिक मात्रा को दर्शाते हैं। चूंकि चीन के सीमा शुल्क विभाग द्वारा सूचित आयात की मात्रा सर्वाधिक है, इसलिए प्राधिकारी को चीन के सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों पर विचार करना चाहिए।
- (4) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई सूचना की तुलना से ऐसा पता चलता है कि भारत में चीन से विचाराधीन उत्पाद के अत्यधिक मात्रा में निर्यात हुए हैं और ऐसे निर्यात, भारतीय सीमा शुल्क विभाग में प्रतिबिंबित कीमतों से काफी कम कीमतों पर हुए हैं।

वर्ष	मात्रा- मी. टन			दर/कि.ग्रा.		
	डीजीसीआई एंड एस (टी.टी)	आईबी आई एस	चीन सीमा शुल्क	डीजीसीआईएंड एस (टी.टी)	आईबी आई एस	चीन सीमा शुल्क
2010-11	182	253	186	428	449	421
2011-12	188	122	166	459	496	452
2012-13	115	144	174	503	497	433
जांच अवधि	105	55	202	634	730	513
जांच अवधि (वार्षिकीकृत)	70	36	134	634	730	513

* चीन के सीमा शुल्क की कीमतें सीआईएफ स्तर पर हैं।

- (5) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए पाटन और क्षति मार्जिन के प्रयोजनार्थ आयात की मात्रा और कीमत का निर्धारण, चीन के सीमा शुल्क विभाग की कीमतों के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है।
- (6) अनेक वर्षों से सूचित किए जा रहे निर्यातों की मात्रा का विश्लेषण करने से ऐसा पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क के लागू होने के बावजूद संबद्ध देश के मामले में आयातों की मात्रा अत्यधिक बनी हुई है। वर्तमान प्रवृत्त से ऐसा पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों की मात्रा में वृद्धि होने की सभी संभावनाएं हैं। इस समय आयातों की अत्यधिक मात्रा पर विचार करते हुए ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों की मात्रा में गिरावट आएगी।

आयात की मात्रा (मी. टन)

विवरण	चीन जनवादी गणराज्य से आयात
2005-06	188
2006-07	194
2007-08	220
2008-09	225

2009-10	433
2010-11	187
2011-12	169
2012-13	176
जांच अवधि	138

*वर्ष 209-10 तक आईबीआईएस पर तथा उसके बाद चीन के सीमा शुल्क विभाग पर आधारित ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

18. इस निवेदन के संबंध में कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने से इत्रसाजी सम्मिश्रण, प्रसाधन सामग्री, अगरबत्तियों (सुगंधित बत्तियों) आदि की लागत बढ़ जाएगी और उनके निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी उपाय करने का उद्देश्य घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापारिक पद्धतियों से घरेलू उद्योग के लिए समान व्यापारिक कार्य क्षेत्र सृजित करना है। पाटन-रोधी उपाय लागू करने से किसी भी तरीके से संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

19. इस निवेदन के संबंध में कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने से उत्पादकों के समूह के गठन को प्रोत्साहन मिलेगा और इसलिए यह न्यायोचित, उचित और न्यूनतम होना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा जांच में शुल्क को निरंतर लागू करने की सिफारिश संभावित विश्लेषण पर आधारित है। प्राधिकारी ने जांच अवधि और पश्च जांच अवधि के लिए पाटन और क्षति के साथ-साथ तृतीय देश के संबंध में जांच की है। जबकि जांच से ऐसा पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का निरंतर पाटन होता रहा है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने पर ऐसे पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, यदि संबद्ध देश से जिस कीमत पर तृतीय देशों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात की जा रहा है, उसी कीमत पर भारत में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया जाता है।

20. जैसा कि इस निर्णय में पहले स्पष्ट कर दिया गया है, प्राधिकारी ने जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ प्रथम दृष्टया प्रमाण के रूप में आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आईबीआईएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है। जांच शुरू करने के बाद महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि जांच अवधि और जांच अवधि पश्चात सहित क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के कारोबार-वार आयात के ब्यौरों की व्यवस्था करें और यह ब्यौरे प्राधिकारी को प्राप्त हो गए हैं। जांच अवधि के दौरान भारत में चीन से आयातों की मात्रा की जांच, विश्व व्यापार एटलस (डब्ल्यूटीए) के आंकड़ों से की गई है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग, डीजीसीआईएंडएस और विश्व व्यापार एटलस जैसे विभिन्न स्रोतों से यथा द्वारा प्रदत्त आयातों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मात्रा – मी. टन				दर रुपए/कि.ग्रा.			
	डीजीसीआई एंड एस	आईबीआईएस	चीन सीमा शुल्क	डब्ल्यूटीए	डीजीसीआई एंड एस	आईबीआईएस	चीन सीमा शुल्क	डब्ल्यूटीए
जांच अवधि	110	55	207	207	673	730	538	538

21. प्राधिकारी ने नोट किया है कि आईबीआईएस, डीजीसीआईएंडएस और चीन के सीमा शुल्क से प्राप्त आयात के आंकड़ों के बीच व्यापक अंतर विद्यमान है। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा यथा प्रस्तुत चीन के सीमा शुल्क आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिक समुद्री विक्रियों से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकारी ने मौजूदा जांच में डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त हुए आयात के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

22. निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई निवेदन नहीं किया गया है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

23. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। किसी भी देश ने चीन को व्यापक मूल्यांकन प्राचलों का अनुसरण करने के बाद बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का दर्जा नहीं दिया है।
- (2) चीन के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार किया जाना चाहिए।
- (3) विश्व में केवल भारत और चीन विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक हैं। ऐसा कोई अन्य देश नहीं है, जिसे भारत में तृतीय देश से कीमत के विचारार्थ तृतीयक देश का प्रतिनिधि बनाया जाए। इस प्रकार सूचना अनुपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भारत को चीन के उत्पादकों के लिए एक उपयुक्त प्रतिनियुक्त देश के रूप में मानने के लिए विचार किया जा सकता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

चीन जनवादी गणराज्य में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत तीन वर्षों में चीन जनवादी गणराज्य को विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों द्वारा पाटन-रोधी जांच करने में एक गैर-अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। इसलिए पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 पैरा 8 (2) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है, बशर्ते कि निर्यातक देश अथवा किसी उत्पादक/निर्यातक द्वारा उपरोक्त नियमावली के अनुसार इस खंडन नहीं कर दिया जाता है।

25. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 पैरा 8 (2) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार किसी उसे गैर-अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने की ऐसी अवधारणा का खंडन किया जा सकता है, यदि चीन जनवादी गणराज्य के निर्यातक, पैरा 8 के उप-पैरा(3) में विनिश्चित मानदंड के आधार पर सूचना और पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करें। चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिपादन प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप-पैरा(3) में उल्लिखित आवश्यक सूचना/प्रमाण प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं, जिनसे प्राधिकारी यह विचार करने के लिए निम्नलिखित मानदंड पर विचार करने में सक्षम हो सकें कि क्या -

- (क) कच्चे माल सहित कीमतों, लागतों और इनपुट, प्रोद्योगिकी की लागत और श्रमिक, आउटपुट, विक्रियों और निवेश के बारे में चीन जनवादी गणराज्य में संबंधित फर्मों के निर्णय, बाजार के संकेतों के उत्तर में हैं जो कि आपूर्ति और मांग की स्थिति को प्रतिबिंबित करते हैं और ये इस संबंध बिना किसी राज्य के हस्तक्षेप के हैं और क्या प्रमुख इनपुट की लागतें बाजार मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं।
- (ख) ऐसी फर्मों के उत्पादन की लागतें और वित्तीय स्थिति, भूतपूर्व गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से अत्यधिक विकृतियों के अधीन हैं, विशेष कर परिसम्पतियों में मूल्यहास होने, अन्य बड़े खाते डालने, व्यापारिक विनिमय तथा ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतार करने के मामले में।
- (ग) ऐसी फर्में दिवालिएपन और परिसम्पति कानूनों के अधीन हैं, जो कि फर्मों की प्रचालन के लिए कानूनी सुनिश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।
- (घ) विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते हैं।

26. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ-7 में उल्लिखित व्यवस्था निम्नानुसार है :-

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रशस्त उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।”

27. इन नियमों के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित किसी भी आधार पर किया जा सकता है :-

- (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में प्रचलित कीमत के आधार पर अथवा
- (ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में संरचित मूल्य के आधार पर अथवा
- (ग) किसी तृतीय देश से भारत सहित किसी अन्य देश की प्रचलित कीमत के आधार पर अथवा
- (घ) यदि उपरोक्त विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी भी अन्य उपयुक्त आधार पर कर सकते हैं, जिनमें समान उत्पाद के लिए भारत में अदा की गई ऐसी वास्तविक कीमत अथवा देय कीमत शामिल है, जिसमें उचित लाभ मार्जिन को विधिवत संमजित किया गया हो।

28. याचिकादाता ने यह दावा किया है कि चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण, (क) भारत में तृतीय देश से आयात कीमत पर और (ख) भारत में उत्पादन की लागत पर किया जा सकता है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और लाभ का विधिवत् समायोजन किया गया हो। याचिकादाता ने आगे यह भी दावा किया है कि चूंकि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए ये विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया “किसी अन्य आधार” पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे “किसी अन्य आधार” के विकल्प को तभी लागू किया जा सकता है, जब कानून के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी अन्य आधार को लागू नहीं किया जा सकता हो। तथापि, मौजूदा मामले में अन्य आधार पर सूचना उपलब्ध है और इसलिए “किसी अन्य आधार” को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जांच शुरू करने की सूचना जारी करने के परिणाम स्वरूप चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी उत्पादक अथवा निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली अथवा बाजार अर्थव्यवस्था प्रतिपादन (एमईटी) का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और न ही कोई निवेदन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी तृतीय देश में कोई अन्य ज्ञात उत्पादक नहीं है, जिसे चीन जनवादी गणराज्य में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के रूप में चयनित किया जा सके। इसके अतिरिक्त किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई निवेदन नहीं किया है और आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ऐसी स्थिति में नहीं है कि नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 को लागू किया जा सके और इसलिए वे नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना करने की आगे कार्रवाई करते हैं।

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान परिस्थितियों में भारत को चीन के उत्पादकों के लिए एक उपयुक्त प्रतिनियुक्त देश के रूप में माना जा सकता है, जिसके फलस्वरूप सही और पर्याप्त सूचना का उपयोग किया जा सकता है। अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा भी भारत को एक उपयुक्त प्रतिनियुक्त देश के रूप में माना

गया है। ऐसी परिस्थितियों में प्राधिकारी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना करने की आगे कार्रवाई करते हैं।

31. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार प्राधिकारी ने कारगर खपत मानदंडों और घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत के आधार पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागतों और उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के बाद चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य की संरचना की है।

छ. निर्यात कीमत

32. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुच्छेद 9 क (1) (ख) के अनुसार किसी वस्तु के संबंध में “निर्यात कीमत” का तात्पर्य इस प्रकार से है :-

“किसी वस्तु के संबंध में “निर्यात कीमत” का तात्पर्य निर्यातक देश अथवा क्षेत्र से निर्यातित वस्तु की कीमत से है और ऐसे मामलों में जिनमें निर्यात कीमत विद्यमान नहीं है अथवा जिनमें निर्यात कीमत अविश्वसनीय है, क्योंकि निर्यातक और आयातक अथवा तृतीय पक्षकार के बीच में सहयोग अथवा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था कायम नहीं है, उस कीमत के आधार पर निर्यात कीमत संरचित की जा सकती है, जिस पर आयातित वस्तु को पहले किसी स्वतंत्र क्रेता को दुबारा बेचा गया है अथवा यदि किसी स्वतंत्र क्रेता को वस्तु को दुबारा नहीं बेचा जाता है अथवा जिसे आयातित दशा में दुबारा नहीं बेचा जाता है, तो उस स्थिति में उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार उचित आधार पर उसका निर्धारण किया जा सकता है।”

33. प्राधिकारी का जांच अवधि के लिए विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए निर्यात कीमत का निर्धारण करने का प्रस्ताव है। चूंकि विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार निर्यात कीमत, एफओबी कीमत है, प्राधिकारी ने ऐसे व्ययों के लिए सामान्य समायोजन करने पर विचार किया है, जो कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के लिए निर्यातकों द्वारा किए गए हों। प्राधिकारी ने कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन के व्ययों, अंतरदेशीय भाड़े के प्रभारों और वीएटी के अंतर के लिए उपयुक्त समायोजन किया है।

ज. पाटन मार्जिन

34. प्रस्तावित सामान्य मूल्य और उपरोक्त अनुसार यथा निर्धारित निर्यात कीमत पर विचार करते हुए प्राधिकारी द्वारा जांच अवधि के लिए निर्धारित किया गया प्रस्तावित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है :-

विवरण	यूनिट	जांच अवधि
संरचित सामान्य मूल्य	यूएस\$/कि.ग्रा.	***
निबल निर्यात कीमत	यूएस\$/कि.ग्रा.	***
पाटन मार्जिन	यूएस\$/कि.ग्रा.	***
पाटन मार्जिन	%	***
पाटन मार्जिन	सीमा %	0-10

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान प्रस्तावित पाटन मार्जिन हालांकि पर्याप्त नहीं है, लेकिन धनात्मक है, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगा हुआ है, लेकिन वह प्रभावी नहीं है तथा पाटन-रोधी शुल्क के लागू होने के बावजूद निरंतर पाटन हो रहा है।

36. प्राधिकारी ने जांच अवधि पश्चात की अवधि से संबंधित आंकड़ों की उपयुक्त जांच की है और जांच अवधि पश्चात की अवधि के दौरान संभावित पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है, जो कि निम्नानुसार है :-

विवरण	यूनिट	जांच अवधि
संरचित सामान्य मूल्य	यूएस\$/कि.ग्रा.	***
निबल निर्यात कीमत	यूएस\$/कि.ग्रा.	***
पाटन मार्जिन	यूएस\$/कि.ग्रा.	***
पाटन मार्जिन	%	***
पाटन मार्जिन	सीमा %	5-15

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि पश्चात की अवधि के दौरान संभावित पाटन मार्जिन धनात्मक नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त है।

38. प्राधिकारी ने विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों से जांच अवधि के दौरान तृतीय देशों को चीन के निर्यातों के प्रभावों की भी जांच की है और तृतीय देश के आंकड़ों की दृष्टि से संभावित पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है, जो कि निम्नानुसार है :-

विवरण	यूनिट	जांच अवधि
संरचित सामान्य मूल्य	यूएस\$/कि.ग्रा.	***
निबल निर्यात कीमत	यूएस\$/कि.ग्रा.	***
पाटन मार्जिन	यूएस\$/कि.ग्रा.	***
पाटन मार्जिन	%	***
पाटन मार्जिन	सीमा %	15-25

39. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तृतीय देश के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया संभावित पाटन मार्जिन भी पर्याप्त है। विश्व व्यापार संगठन की एटलस के आंकड़ों से प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन के विचाराधीन उत्पाद के निर्यात की औसत निबल निर्यात कीमत, विश्व में है। जांच अवधि के दौरान चीन के लिए निर्धारित अमरीकी डालर ***/कि.ग्राम के रूप में प्रस्तावित सीएनवी पर विचार करते हुए, पाटन न केवल धनात्मक है, बल्कि यह पर्याप्त भी है। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में यदि चीन भारत में विचाराधीन उत्पाद का उसी औसत कीमत पर निर्यात करता है, जिस कीमत पर चीन विश्व के बाजार में निर्यात कर रहा है, तो उसके परिणाम स्वरूप पाटन गहन और पर्याप्त हो जाएगा। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन होने की संभावना इस तथ्य पर विचार करते हुए और अधिक बढ़ जाएगी कि मौजूदा जांच में घरेलू उद्योग देश में विचाराधीन उत्पाद का एक मात्र उत्पादक है और चीन के पास अत्यधिक उत्पादन क्षमता होने तथा निर्यात करने के प्रति अभिरुचि होने के कारण विश्व बाजार में वास्तविक एकाधिकार प्राप्त है। यह कहना गलत नहीं है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में भारत में अकेले घरेलू उद्योग को चीन से होने वाले गहन पाटन की पुनरावृत्ति होने की स्थिति में बंद होना पड़ हो सकता है।

झ. क्षति का निर्धारण करने तथा क्षति और क्षति के संबंध की जांच करने के लिए कार्यप्रणाली

निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

40. क्षति का निर्धारण करने तथा क्षति और क्षति के संबंध की जांच करने के लिए कार्यप्रणाली के बारे में निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई निवेदन नहीं किया गया है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

41. इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद चीन से निरंतर आयात हो रहे हैं।
- (2) विभिन्न आर्थिक प्राचलों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन स्थिर हुआ है अथवा उसमें सुधार हुआ है। तथापि, आयात की मात्रा अत्यधिक बनी हुई है।
- (3) पाटन-रोधी शुल्क लागू नहीं होने की स्थिति में आयातों से घरेलू कीमत में कटौती होगी।
- (4) पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर देने से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि चीन जनवादी गणराज्य से अत्यधिक निर्यात होने के फलस्वरूप यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका में घरेलू उत्पादन बंद हो गया है।
- (5) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद घरेलू बाजार में पाटित कीमतों पर आयात किए गए हैं। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटित संबद्ध वस्तुओं के आयातों में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है।
- (6) संबद्ध देश के उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमता है जिससे यह स्थापित होता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर देने पर भारत में निर्यात गहन होंगे।
- (7) संबद्ध देश के निर्यातक, तृतीय देशों को पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद के निर्यात कर रहे हैं।
- (8) वर्तमान जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और अत्यधिक है।
- (9) आयात कीमतें वास्तव में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम हैं और साथ ही ये पाटन-रोधी शुल्क के मानक से कम हैं। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में उपभोक्ता आयातित उत्पाद की ओर प्रवृत्त होंगे जिसके फलस्वरूप उत्पाद के आयातों में अत्यधिक वृद्धि होगी।
- (10) पाटित आयातों की अत्यधिक मात्रा, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम कीमतों पर है और इसलिए इसके फलस्वरूप कीमत में ह्रास और कीमत न्यूनीकरण होने की संभावना है। यदि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए अपनी बिक्री कीमत में और कटौती करनी पड़ेगी जिससे उसे बिक्रियों की लागत से कम कीमत पर अपने उत्पाद बेचने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप उसे घोर कीमत क्षति होगी।
- (11) ऐसी स्थिति में जिसमें विभिन्न कारोबारों में आयात कीमत में इतना अधिक अंतर होता है, जैसा कि मौजूदा मामले में है, घरेलू उद्योग को निम्नतर आयात कीमत पर स्वतः मानक बनाने की आवश्यकता होगी। उपभोक्ता इस अवधि में सूचित औसत कीमतों पर विचार नहीं करेंगे। उपभोक्ता इस अवधि में सूचित निम्नतम कीमत पर विचार करेंगे। इस प्रकार वास्तव में इस अवधि में उच्च कीमतों पर अत्यधिक आयात होते हैं, जो कि घरेलू उद्योग के लिए लाभप्रद होते हैं। घरेलू उद्योग के लिए वह कीमत प्रासंगिक है जिस पर चीन के उत्पादक कीमतों को कम कर सकते हैं और जिन पर वे उत्पाद बेच सकते हैं।

प्राधिकारी द्वारा जांच

42. अनुबंध-2 के साथ पठित साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए", ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।

43. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उपरोक्त नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, बिक्रियों की निबल वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर विचार किया गया है।

44. वर्तमान जांच, लागू पाटन-रोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा जांच है। नियम 23 में ऐसी व्यवस्था है कि यथावश्यक परिवर्तन सहित नियम 11 के उपबंध समीक्षा के मामले में भी लागू होंगे। इसलिए प्राधिकारी ने अनुबंध-2 के साथ पठित यथावश्यक परिवर्तन सहित नियम 11 के उपबंध पर विचार करते हुए क्षति का निर्धारण किया है। इसके अतिरिक्त चूंकि विचाराधीन उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क लगे हुए हैं, प्राधिकारी ने इस पर विचार किया है कि घरेलू उद्योग की क्षति की जांच करते समय क्या संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए मौजूदा पाटन-रोधी शुल्कों पर विचार करने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने इसकी भी जांच की है कि क्या विद्यमान पाटन-रोधी शुल्क ऐसे पाटन को रोकने के लिए पर्याप्त हैं अथवा नहीं जिनसे क्षति हो रही है।

45. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 (क) (5) के अनुसार लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों को यदि पहले समाप्त नहीं कर दिया जाता है, तो ऐसे शुल्कों को लागू करने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार का उनकी समीक्षा करने पर ऐसा विचार है कि ऐसे शुल्क को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, वह समय-समय पर ऐसे शुल्क की प्रभावी अवधि को पांच वर्ष तक आगे बढ़ा सकती है और ऐसी अवधि ऐसे विस्तार करने के आदेश के जारी होने की तारीख से शुरू होगी।

46. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभावों तथा कीमतों और लाभप्रदता पर पड़ने वाले उनके प्रभावों की जांच की है, ताकि विद्यमान क्षति तथा पाटन और क्षति के बीच यदि कोई कारणात्मक संबंध है, तो उसकी जांच की जा सके। प्राधिकारी ने मेसर्स एटलस फाईन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड (जो कि इस समय मेसर्स एम्स इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात है), जो कि नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग बनता है, से संबंधित सूचना पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की हुई क्षति की जांच की है। तदनुसार पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव की जांच की है, जो कि निम्नानुसार है :-

मात्रा के प्रभाव

मांग और बाजार का हिस्सा

47. भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत, घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों का योगफल है, जैसा की नीचे तालिका में दिया गया है।

भारत में मांग	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि वार्षिकीकृत	अप्रैल, 2013 – सितंबर, 2014 (जांच अवधि)	जांच अवधि पश्चात वार्षिकीकृत	जांच अवधि पश्चात
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	107	181	265	265	239	239
आयात –संबद्ध देश	मी.टन	283.13	191.04	128.79	57.48	106.95	77.20	38.60
आयात –अन्य देश	मी.टन	257.00	5.40	0.01	0.01	2.90	3.83	1.92
कुल मांग	मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	51	57	65	65	63	63
बाजार का हिस्सा								
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***	***	***
सीमा	%	15-25	40-50	60-70	80-90	80-90	75-85	75-85
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***	***	***	***
संबद्ध देश	%	41.21	54.08	32.62	12.86	15.40	17.85	17.85
अन्य देश	%	37.41	1.53	0.00	0.00	0.42	0.89	0.89

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समस्त क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। इसी प्रकार घरेलू उद्योग की बिक्रियों और बाजार के हिस्से में भी वृद्धि हुई है।

आयात की मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

49. पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव के बारे में प्राधिकारी को इसकी जांच करने की आवश्यकता होती है कि क्या पाटित आयातों में पूर्णरूपेण अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के प्रसंग में अत्यधिक वृद्धि हुई है। नीचे तालिका में दी गई सूचना से ऐसा पता चलता है कि क्षति अवधि के दौरान चीन से आयातों में पर्याप्त रूप से गिरावट आई है, लेकिन वे अभी भी पाटित कीमतों पर निरंतर हो रहे हैं तथा जांच अवधि के बाद उनमें वृद्धि होने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है।

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि वार्षिकीकृत	अप्रैल 2013 – सितंबर 20 14 (जांच अवधि)	जांच अवधि पश्चात वार्षिकीकृत	जांच अवधि पश्चात
आयात-चीन जनवादी गणराज्य	मी.टन	283.13	191.04	128.79	57.48	106.95	77.20	38.60
आयात-अन्य देश	मी.टन	257.00	5.40	0.01	0.01	2.90	3.83	1.92
कुल आयात	मी.टन	540.13	196.44	128.80	57.49	109.84	81.03	40.52
निम्न के प्रसंग में बाजार का हिस्सा								
कुल आयात	%	78.62	55.61	32.62	12.86	15.82	18.73	18.73
याचिकादाता का उत्पादन	%	***	***	***	***	***	***	***
सीमा	%	15-25	40-50	60-70	80-90	80-90	75-85	75-85

कीमत के प्रभाव

50. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में नियमावली के अनुबंध-2 (ii) में उल्लिखित व्यवस्था निम्नानुसार है :-

“जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।”

कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री

51. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी ने इस पर विचार किया है कि क्या पाटित आयातों द्वारा कीमत में अत्यधिक कटौती हो रही है, जब उसकी तुलना भारत में समान वस्तु/उत्पाद की कीमत से की जाती है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव अन्यथा कीमतों को अत्यधिक सीमा तक ह्रास करते अथवा कीमतों में ऐसी वृद्धि होने को रोकते, जो कि अन्यथा काफी अधिक सीमा तक होती। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर आयात कीमतों के कम कीमत पर बिक्री होने के प्रभाव का भी मूल्यांकन किया है, जो कि निम्नानुसार है :-

विवरण	यूओएम	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि वार्षिकीकृत	अप्रैल, 2013 से सितंबर, 2014 (जांच अवधि)	पश्च जांच अवधि
क्षति रहित कीमत	रुपए/मी.टन	***	***	***	***	***	***
निबल बिक्री वसूली	रुपए/मी.टन	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100.00	103.15	104.36	113.26	113.26	115.65
आयातों का पहुंच मूल्य	रुपए/मी.टन	345	505	602	689	689	629
कीमत कटौती	रुपए/मी.टन	***	***	***	(***)	(***)	***
कीमत कटौती का %	%	***	***	***	(***)	(***)	***
कीमत कटौती की सीमा	%	70-80	20-30	0-10	(0-10)	(0-10)	5.15
कम कीमत पर बिक्री	रुपए/मी.टन	***	***	***	(***)	(***)	(***)
कम कीमत पर बिक्री का %	%	***	***	***	(***)	(***)	(***)
कम कीमत पर बिक्री की सीमा	%	-	-	-	(5-15)	(5-15)	(0-10)

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान कीमत में कटौती नकारात्मक है, लेकिन जांच अवधि पश्चात यह सकारात्मक है। लेकिन जांच अवधि तथा जांच पश्चात अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री नकारात्मक रही है।

कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और निबल बिक्री कीमत की आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। जांच अवधि तथा जांच पश्चात अवधि के दौरान आयात कीमतों में ह्रास अथवा कीमत न्यूनीकरण नहीं कर रहे हैं।

विवरण	यूओएम	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि वार्षिकीकृत	अप्रैल, 2013 से सितंबर, 2014 (जांच अवधि)	पश्च जांच अवधि
बिक्रियों की लागत	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	109.36	105.25	106.05	106.05	107.10
बिक्री लागत	रुपए/कि.ग्रा.	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	103.15	104.36	113.26	113.26	115.65
पहुंच मूल्य	रुपए/कि.ग्रा.	345	505	602	689	689	629
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	174	200	200	182

ज. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक प्राचलों की जांच

53. पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध- के अनुसार क्षति का निर्धारण करने में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर संबद्ध वस्तुओं के आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्य पूर्ण जांच करना निहित है। उक्त नियम के संबद्ध उद्धृण को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है :-

"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट, सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

54. तदनुसार घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक प्राचलों नीचे विश्लेषण किया गया है।

बिक्री, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग

55. घरेलू उद्योग की बिक्रियों, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :-

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि वार्षिकीकृत	अप्रैल, 2013 से सितंबर, 2014 (जांच अवधि)	पश्च जांच अवधि वार्षिकीकृत	पश्च जांच अवधि
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	100	100	107	107	120	120
उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	100	141	253	253	216	216
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***	***	***
सीमा	%	25-35	25-35	40-50	70-80	70-80	50-60	50-60
घरेलू बिक्रियां	मी.टन	147	157	266	390	584	352	176
	प्रवृत्ति	100	107	181	265	265	239	239
मांग	मी.टन	***	***	***	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	100	51	57	65	65	63	63

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समस्त क्षति अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग में वृद्धि दृष्टिगत हुई है। जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में वृद्धि की है।

बाजार का हिस्सा

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि समग्र क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार के हिस्से में वृद्धि हुई है और संबद्ध देश के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। तथापि, जांच पश्चात अवधि में संबद्ध देश के बाजार हिस्से में वृद्धि होने की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है।

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***
चीन	%	41.21	54.08	32.62	15.07	17.85

अन्य देश	%	37.41	1.53	0	0.76	0.89
----------	---	-------	------	---	------	------

लाभ/हानि, नकदी प्रवाह, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ

58. लाभ/हानि, नकदी प्रवाह, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ से संबंधित सूचना नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि वार्षिकीकृत	अप्रैल, 2013 से सितंबर, 2014 (जांच अवधि)	पश्च जांच अवधि वार्षिकीकृत	पश्च जांच अवधि
प्रति यूनिट लाभ/हानि	रुपए./कि.ग्रा.	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	41	95	185	185	201	201
घरेलू बिक्रियों पर लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	44	173	490	490	480	480
व्याज और कर पूर्व लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	44	173	540	540	538	538
नकदी लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	59	183	469	469	476	476
निवेश पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	30	95	221	221	216	216

59. प्राधिकारी उपरोक्त तालिका से नोट करते हैं कि समस्त क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप समस्त क्षति अवधि के दौरान लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ में सुधार दृष्टिगत हुआ है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि कर सकता है तथा लाभ अर्जित कर सकता है।

मालसूचियां

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान बिक्रियों की मात्रा में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग के औसत माल सूची स्तर में गिरावट आई है।

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	अप्रैल, 2013 से सितंबर, 2014 (जांच अवधि)	जांच अवधि पश्चात्
औसत भंडार	मी.टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	103	56	30

रोजगार, वेतन और उत्पादकता

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रोजगार में गिरावट आई है, लेकिन वेतन बढ़ गए हैं। घरेलू उद्योग की उत्पादकता में बढोत्तरी दृष्टिगत हुई है।

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि वार्षिकीकृत	अप्रैल, 2013 से सितंबर, 2014 (जांच अवधि)	पश्च अवधि वार्षिकीकृत	पश्च जांच अवधि
रोजगार	संख्या	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	86	91	91	91	91
वेतन	लाख रुपए	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	87	111	137	137	174	174
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी.टन/ संख्या	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	163	278	278	238	238
उत्पादकता प्रति दिन	मी.टन/ दिन	***	***	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	141	254	254	217	217

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों की तुलना में आयातों का पहुंच मूल्य मामूली अधिक है, जिसके फलस्वरूप नकारात्मक कीमत कटौती हुई है। तथापि, जांच पश्चात अवधि के दौरान कीमत में कटौती सकारात्मक बन गई है और यह पर्याप्त है। चूंकि आयातों का एक मात्र स्रोत चीन है तथा विचाराधीन उत्पाद का कोई प्रतिस्थापन नहीं है, शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर चीन की पाटित कीमतों से घरेलू उद्योग की कीमतों में घोर कटौती होगी।

पाटन की मात्रा

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक है, जिससे ऐसा स्पष्ट होता है कि पाटन-रोधी शुल्क लगे होने के बावजूद यह मामला निरंतर पाटन होने का है।

संवृद्धि

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग ने मात्रा और कीमत प्राचलों दोनों ही रूप में वृद्धि दर्शाई है। तथापि, जांच पश्चात अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में गिरावट आई है, जिसका अभिप्राय यह है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर घरेलू उद्योग की संवृद्धि में गिरावट आएगी।

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि	जांच अवधि पश्चात
उत्पादन	%	-	(0.46)	41.09	80.14	(14.47)
घरेलू बिक्रियां	%	-	6.76	69.61	46.47	(9.78)
बिक्रियों की लागत	%	-	9.36	(3.75)	0.76	0.99
बिक्री कीमत	%	-	3.15	1.17	8.52	2.11
लाभप्रदता	%	-	(55.77)	290.89	183.70	(2.07)

निवेश पर प्रतिलाभ	%	-	(69.56)	212.11	132.51	(2.07)
-------------------	---	---	---------	--------	--------	--------

पूँजीगत निवेश जुटाने की क्षमता

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान अपनी क्षमता बढ़ाई है।

ट. कारणात्मक संबंध

66. प्राधिकारी ने इसकी जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, जो कि निम्नानुसार है :-

- (क) **पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य** :- प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य स्रोतों से आयात बहुत नकारात्मक हैं, जिनका भारतीय बाजार में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।
- (ख) **मांग में संकुचन** :- प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। क्षति अवधि के दौरान उत्पाद की मांग बढ़ी है। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमता का विस्तार किया है।
- (ग) **खपत के पेटर्न में परिवर्तन** :- विचाराधीन उत्पाद के खपत पेटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (घ) **खपत के पेटर्न में परिवर्तन** :- प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का स्वतंत्र रूप से आयात हो रहा है। घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का एक मात्र उत्पादक है और घरेलू उत्पादन और बिक्रियों में उसका अत्यधिक अंशदान होता है।
- (ङ) **प्रोद्योगिकी में विकास** :- प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रोद्योगिकी में ऐसे किसी विशेष परिवर्तन का पता चले, जो कि घरेलू उद्योग की क्षति का कारण हो सकता है।
- (च) **निर्यात निष्पादन** :- घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग हुई क्षति का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ घरेलू और निर्यात बाजार में कीमत और लाभप्रदता को पृथक कर दिया है।

ठ. पाटन और क्षति के निरंतर जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

67. घरेलू उद्योग ने पाटन और क्षति के निरंतर होने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के दावे के समर्थन में निम्नलिखित निवेदन किए हैं :-

- (1) जांच अवधि के दौरान अत्यधिक पाटन मार्जिन से ऐसा सिद्ध होता है कि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में ऐसे पाटन के निरंतर बने रहने और अधिक गहन होने की संभावना है।
- (2) पाटन-रोधी शुल्क के विद्यमान होने पर भी संबद्ध देश से आयात अत्यधिक बने हुए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में उनमें वृद्धि होगी।
- (3) संबद्ध देश के उत्पादकों के पास कोऊमेरीन का उत्पादन करने की अत्यधिक क्षमता विद्यमान है। पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त हो जाने की स्थिति में आयातों की मात्रा में और वृद्धि होगी।
- (4) संबद्ध विदेशी उत्पादकों के पास अत्यधिक बेशी उत्पादन क्षमताएं उपलब्ध हैं, जिसके प्रमाण का उपरोक्त जांच से पता चलता है। उपलब्ध रिकार्ड के प्रमाण से यह स्पष्ट पता चलता है कि संबद्ध देश के विदेशी उत्पादकों के पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है, जैसे कि-

“ऐसा विश्वास है कि मूल जांच के दौरान चीन में कोऊमेरीन का उत्पादन करने वाले उद्योग में 3 बड़े उत्पादक शामिल हैं और 10 छोटी फर्में हैं। याचिका के अनुसार इन तीनों उत्पादकों (नामत: टिआंजिन नंबर 1, चांगझाऊ नंबर 2 संयंत्र और शंघाई परफ्यूमरी) की संयुक्त वार्षिक क्षमता 3.1 मिलियन पाउंड है और इनका वर्तमान वार्षिक उत्पादन लगभग 1.9 मिलियन पाउंड है। संबद्ध उत्पाद के 10 छोटे उत्पादकों की संयुक्त क्षमता लगभग 700,00 पाउंड होने तथा उत्पादन लगभग 500,000 पाउंड होने का अनुमान है। इसलिए चीन का कोऊमेरीन का उत्पादन करने वाले उद्योग की कुल क्षमता लगभग 3.7 मिलियन पाउंड, 2.4 मिलियन के 52 उत्पादन, 65 प्रतिशत क्षमता उपयोग होने तथा अनप्रयुक्त क्षमता के लगभग 1.3 मिलियन पाउंड होने का अनुमान लगाया गया है।”

- (5) संबद्ध देश से निर्यातकों का विश्वभर में बहुत अधिक निर्यात अभिमुखीकरण है। इसलिए यदि मौजूदा पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो पाटन और क्षति की बदतर स्तर पर पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- (6) पाटन-रोधी शुल्क नहीं होने की स्थिति में आयातों के पहुंच मूल्य, घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती करेंगे। इसलिए पाटन-रोधी शुल्कों के समाप्त कर दिए जाने से घरेलू उद्योग पर अत्यधिक प्रतिकूल मात्रात्मक और कीमत प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- (7) संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के फलस्वरूप यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका में घरेलू उत्पादन बंद हो गया है।
- (8) वर्तमान स्थिति से ऐसा स्पष्ट पता चलता है कि पाटन-रोधी शुल्कों के समाप्त कर दिए जाने पर पाटन गहन होगा। याचिकादाता का यह निवेदन है कि जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन का स्तर न्यूनतम से अधिक नहीं बल्कि बहुत अधिक था। पूर्व जांच के समय प्रचलित परिस्थितियां अभी भी विद्यमान हैं। उनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उपरोक्त ऐसा निर्धारण कि चीन जनवादी गणराज्य से अत्यधिक निर्यात होने के फलस्वरूप यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका में घरेलू उत्पादन बंद हो गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

68. वर्तमान जांच के चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते प्राधिकारी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या पाटन-रोधी शुल्कों को निरंतर जारी रखे जाने की आवश्यकता है। साथ ही इसकी जांच करने की भी आवश्यकता है कि क्या लगाया गया शुल्क, क्षति पाटन को समाप्त करने के उद्देश्य को पूरा कर रहा है।

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा जांच में पाटन-रोधी शुल्क लगे होने के बावजूद निरंतर पाटन हो रहा है। जांच पश्चात अवधि और तृतीय देश के आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर पाटन के गहन होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जैसा कि घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है, चीन के पास विशाल निर्यात अभिमुखीकरण के साथ विचाराधीन उत्पाद की अत्यधिक क्षमता विद्यमान है। यदि शुल्क को रद्द कर दिया जाता है, तो भारत में एक मात्र घरेलू उद्योग चीन जनवादी गणराज्य से गहन पाटन की पुनरावृत्ति होने से लुप्त हो जाएगा।

70. निम्नलिखित विश्लेषण से उपरोक्त स्थिति की और संपुष्टि हो जाती है :-

विवरण	यूनिट	विश्व व्यापार एटलस के आंकड़ों के अनुसार
तृतीय देशों को निर्यात की कुल मात्रा	मी. टन	5143
पाटित कीमतों पर निर्यात की मात्रा (सीएनवी के साथ तुलना करने पर)	मी. टन	4872
क्षति कीमतों पर निर्यात की मात्रा (घरेलू उद्योग की एनआईपी के साथ तुलना करने पर)	मी. टन	4725

पाटित निर्यातों का हिस्सा	%	94.73
क्षति पहुंचाने वाले निर्यातों का हिस्सा	%	91.87

प्राधिकारी नोट करते हैं कि विश्व बाजार में चीन के 95 प्रतिशत निर्यात पाटित कीमतों पर होते हैं और 92 प्रतिशत निर्यातों के कारण क्षति होती है। इसलिए भारत द्वारा शुल्क को रद्द कर दिए जाने की स्थिति में चीन के निर्यात एक मात्र घरेलू उद्योग को बाजार से बाहर कर देगा।

ड. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

71. जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य की तुलना, प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत के साथ की गई है। जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश के लिए निर्धारित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षति मार्जिन निम्नानुसार है :-

क्षति मार्जिन-जांच अवधि

विवरण	जांच अवधि
	यू.एस. \$/ कि.ग्रा.
क्षति रहित कीमत	***
पहुंच मूल्य	11.35
क्षति मार्जिन	(***)
क्षति मार्जिन (%)	(***)
क्षति मार्जिन (%) सीमा	(5-15)

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन नकारात्मक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जांच अवधि के दौरान जिस कीमत पर चीन से आयात हुए हैं, उनका घरेलू उद्योग पर कोई क्षति प्रभाव नहीं पड़ा है।

73. प्राधिकारी ने जांच के बाद की अवधि के दौरान चीन के आयातों के क्षति के प्रभावों की आगे जांच की है और संभावित क्षति पाटन निर्धारित किया है, जो कि निम्नानुसार है:-

विवरण	जांच अवधि
	यू.एस. \$/ कि.ग्रा.
क्षति रहित कीमत	***
पहुंच मूल्य	10.05
क्षति मार्जिन	(***)
क्षति मार्जिन (%)	(***)
क्षति मार्जिन (%) सीमा	(0-10)

प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच के बाद की अवधि के दौरान संभावित क्षति मार्जिन नकारात्मक है।

74. चूंकि जांच अवधि के दौरान तथा जांच के बाद की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन नकारात्मक रहा है, इसलिए प्राधिकारी ने विश्व व्यापार संगठन एटलस के आंकड़ों के आधार पर तृतीय देशों को चीन की औसत निर्यात कीमत के आधार पर संभावित क्षति मार्जिन का मूल्यांकन किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :-

क्षति मार्जिन-जांच अवधि के दौरान तीसरे देशों से आयात

विवरण	जांच अवधि
	यू.एस. \$/ कि.ग्रा.
क्षति रहित कीमत	***
पहुंच मूल्य	9.86
क्षति मार्जिन	(***)
क्षति मार्जिन (%)	(***)
क्षति मार्जिन (%) सीमा	(0-10)

75. उपरोक्त सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में यदि संबद्ध देश जिस औसत कीमत पर तृतीय देशों को निर्यात करता है, उसी औसत कीमत पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करता है, तो उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

ढ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

76. प्रकटन पश्चात घरेलू उद्योग द्वारा की गई टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :-

- (1) पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी चीन जनवादी गणराज्य से निरंतर पाटन हुआ है।
- (2) विश्व बाजार में चीन जनवादी गणराज्य के 95 प्रतिशत निर्यात पाटित कीमतों पर होते हैं जिसमें 92 प्रतिशत निर्यातों से क्षति हो रही है जैसाकि चीन जनवादी गणराज्य से निर्यातों के आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे निर्यात विश्व बाजार को किए जा रहे हैं।
- (3) पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप पाटन गहन होगा जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
- (4) संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के फलस्वरूप यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राज्य अमरीका में घरेलू उत्पादन बंद हो गया है।
- (5) ऐसी वैश्विक स्थिति में एकमात्र भारतीय उत्पादक का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।
- (6) भारतीय सीमाशुल्क विभाग के आंकड़ों में सूचित आयात कीमत ऐसी कीमत है जो मानक पाटनरोधी शुल्क से पुनः समामेलित की गई हैं और यह आयातों की वास्तविक कीमत को प्रतिबिंबित नहीं करती है।
- (7) निरंतर पाटित आयातों के कारण गहन पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी शुल्क को उसकी विद्यमान मात्रा में तथा यूएस डॉलर के रूप में 5 वर्ष तक की अवधि के लिए और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

77. प्रकटन पश्चात फ्रेगरेस एंड फ्लेवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह बताया है कि वह सुनवाई के स्थगित हो जाने के कारण 6 नवंबर, 2016 को प्राधिकारी द्वारा की गई मौखिक सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकी थी। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि फ्रेगरेस एंड फ्लेवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहित हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 के पत्र द्वारा यह सूचित किया गया था कि मौखिक सुनवाई का आयोजन, 6 नवंबर, 2015 को अपराह्न 3.00 बजे, डीजीएडी के अधिवेशन कक्ष, जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में करना तय किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने हित में इस सुनवाई में संभावित रूप से भाग लेने वाले अपने प्रतिनिधियों के नाम और उनके पते के बारे में सूचित करें। प्राधिकारी ने निर्धारित तारीख, समय और स्थल पर मौखिक सुनवाई की थी। जबकि इस मौखिक सुनवाई में घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और अपने निवेदन किए थे, लेकिन इस मौखिक सुनवाई में फ्रेगरेस एंड फ्लेवर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। इसलिए उनका यह तर्क कि वे मौखिक सुनवाई के स्थगित हो जाने के कारण उसमें भाग नहीं ले सके थे, निराधार है।

निष्कर्ष

78. प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच करने के बाद प्राधिकारी के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं :-

- (1) पाटन-रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद जांच अवधि के दौरान सामान्य मूल्य से कम कीमत पर संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के निर्यात भारत को किए गए हैं।
- (2) जांच अवधि के दौरान और जांच के बाद की अवधि के दौरान हालांकि पाटन निरंतर बना रहा है और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन सकारात्मक है, फिर भी उससे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।
- (3) तृतीय देशों को चीन की कीमतें, पाटित कीमतें हैं और यदि उक्त कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयात, भारत में किए जाते हैं, तो पाटन-रोधी शुल्क के समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग को संभावित क्षति हो सकती है।

ज. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः पाटन-रोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में समान अवसरों वाली स्थिति सृजित करके खुली और उचित प्रतियोगिता की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटन-रोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देश से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए ये उपभोक्ता को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं करेंगे।

80. ऐसा माना जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क लागू करने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और उसके परिणाम स्वरूप इन उत्पादों की सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, पाटन-रोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटन-रोधी उपाय लागू करने से पाटित पद्धतियों को प्राप्त होने वाले अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग में आने वाली गिरावट को रोकेंगे तथा संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक चुनाव करने की सुविधा प्रदान करने में सहायक होंगे।

त. सिफारिश

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और उसके बारे में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सार्थक सूचना प्रदान करने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। अधिनियम और नियमावली के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच की शुरुआत और उसको कारणात्मक संपर्क होने पर तथा जांच अवधि में और जांच के बाद की अवधि में सकारात्मक पाटन सिद्ध हो जाने पर तथा पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में तृतीय देशों को चीन के निर्यातों की कीमतों की तुलना करने पर क्षति की संभावना होने पर, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखना इस मामले में पाटन और क्षति की संभावना को दूर करने के लिए अपेक्षित है। इस जांच परिणाम के मद्देनजर कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन के लगातार होते रहने अथवा बार-बार होते रहने की संभावना है, अतः प्राधिकारी निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

82. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को देखते हुए, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति मार्जिन से कम के बराबर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। यह मानते हुए कि मूल जांच में पाटनरोधी शुल्क संदर्भ कीमत आधार पर लगाया गया था। प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं, संबद्ध देशों से आने वाले अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी आयातों पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हैं और यह उसी तरह से लगाया जाए जैसाकि अधिसूचना सं. 12/2012-सी.शु. (एडीडी) दिनांक 8 फरवरी, 2012 और अधिसूचना सं. 8/2015-सी.शु. (एडीडी) दिनांक 7 अप्रैल, 2015 द्वारा पहले लगाए गए अनुसार उसी रूप और तरीके से आयातों और संदर्भ कीमत के पहुंच मूल्य के बीच अंतर के रूप में हो। तदनुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में दर्शायी गयी राशि और पहुंच मूल्य के बीच अंतर के बराबर चीन जनवादी गणराज्य से आयातित अथवा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्रमांक	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	मापन का यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2932.21	सभी प्रकार के कोऊमेरीन	चीनी जनवादी गणराज्य	चीनी जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	14.02	कि.ग्राम	यू.एस.\$
3	2932.21	सभी प्रकार के कोऊमेरीन	चीनी जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई अन्य देश	चीनी जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	14.02	कि.ग्राम	यू.एस.\$
4	2932.21	सभी प्रकार के कोऊमेरीन	चीनी जनवादी गणराज्य	चीनी जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई अन्य देश	कोई	कोई	14.02	कि.ग्राम	यू.एस.\$

83. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर, सभी शुल्क शामिल होंगे।

थ. आगे की प्रक्रिया

84. केन्द्र सरकार द्वारा इस जांच परिणाम पर आधारित आदेश के विरुद्ध खिलाफ कोई अपील, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2016

FINAL FINDING

Subject: Sun Set Review (SSR) investigation of the anti-dumping duties imposed on the imports of 'Coumarin', originating in or exported from China PR.

F. No. 15/26/2014-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the case

2. An anti-dumping investigation concerning imports of "Coumarin" (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR was initiated by the

Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) vide Notification No.14/17/2009-DGAD dated 10th July 2009. The preliminary finding was issued by the Authority, recommending imposition of provisional anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR, vide Notification No. 14/17/2009-DGAD dated 29th January 2010. The provisional duty was imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR vide Notification No. 38/2010-Customs dated 23rd March 2010. The final findings notification of the Authority was published vide Notification No. 14/17/2009-DGAD dated 7th July 2010. The definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, vide Notification No. 82/2010-Customs dated 20th August 2010.

3. Fragrance and Flavors Association had filed an appeal before CESTAT, challenging the imposition of Anti-dumping duty. The Hon'ble CESTAT vide its order dated 17th June, 2011 set aside the Final Findings and the Customs Notification dated 20th August, 2010 and remanded the matter back to Designated Authority for fresh decision after granting a reasonable opportunity of hearing to the appellant within a period of 6 months. The Authority published the remanded finding vide Notification No. 14/17/2009-DGAD dated 23rd December 2011 and the relevant notification imposing the anti-dumping duty was issued by the Central Government vide Notification No. 12/2012–Customs dated 8th February, 2012.
4. M/s. Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd. which has now been acquired by M/s. Aims Impex Pvt. Ltd. w.e.f. 23rd October 2015 and now known by the name M/s. Aims Impex Pvt. Ltd. (hereinafter also referred to as the petitioner), have filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and consequent injury to the domestic industry and requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the said subject country. Accordingly, the Authority initiated the sunset review (SSR) investigation in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, vide Notification No. 15/26/2014-DGAD, dated 16th March, 2015 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country) and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

B. Procedure

5. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority sent copy of the initiation notification dated 16th March, 2015 to the embassy of the subject country in India, known exporters from the subject country, known importers and other interested parties, and the domestic producer, as per available information. The known interested parties were requested to file questionnaire responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to embassy of the subject country along with a list of known exporters/producers, with a request to advise the exporters/producers from the subject country to respond within the prescribed time.
 - ii. Copy of the non-confidential version of the application filed on behalf of the petitioner was made available to the known exporters, producers and the embassy of the subject country in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - iii. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating the sunset review to the following known producers/exporters in the subject countries and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules:

Tianjin City No. 3, Chemical Reagent factory Xuzhuangzixiang, Dongli District Tianjin–300 240.	Changzhou No. 2 Chemical Plant 16, Changqi Rd., Qishuyan, Changzhou City Jiangsu–213 003.
--	--

Nanjing Huafa Chemical Co. Ltd. Meishan, Zhonghuamenwai Jiangning County Nanjing City Jiangsu– 210 039.	Doumen County Baishifa Chemical Factory Co., Ltd Doumen Town, Doumen County Zhuhai City, Guangdong–519.
--	---

- iv. However, none of the producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire response or made any submissions.
- v. Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to the known producers/exporters in China PR and the Embassy of China PR in India with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit. While for the purpose of initiation, the normal value in China PR was considered based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted, the Authority informed the known producers/exporters from China PR that it proposes to examine the claim of the petitioner in the light of Para 7 and Para 8 of Annexure I of Anti-dumping Rules, as amended. The exporters/producers of the subject goods from China PR were, therefore, requested to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned to enable the Authority to consider whether market economy treatment can be granted to the cooperative exporters/producers in China PR. However, none of the Chinese producers/exporters have filed MET questionnaire response rebutting the non-market economy treatment meted out to China PR.
- vi. Questionnaires were sent to the following known importers/users/ associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with the Rules:

Bharat Industrial Corporation 341/35, 1 st Cross, Dayanand Nagar, Shrirampuram, Bangalore–560 021	Floral Frag. Pvt. Ltd. 1, Bonfield Lane, First Floor, Kolkata–700 001
Eastern Agencies, 301, Mangal Simran, 28 th Road, Off. Turner Road, Bandra (West) Mumbai– 400 050	PBS Frangrances Pvt. Ltd, 25A, Himalaya House, 79, Palton Road, Mumbai–400 001
Tushar Enterprises , 14/A, Maskti Market Near Moti Mahal Hotel, Kalupur, Ahmedabad–380 002	Karnataka Soaps & Detergents Ltd. P.B. No. 5531, Bangalore–Pune Highway Bangalore–560 055
Shalimar Agarbatti, Post Box No. 2114, No. 32 & 33, 3 rd Cross, Shrirampuram, Bangalore– 560 021	Vasu Agarbatti, No. 2203, P.B. No. 390, New Sayyji Rao Road, Mysor, Karnataka
Sachee Aromatics , Y–4, Okha Industrial Area, Phase II, New Delhi–110 020	Gupta & Co., 68, Scindia House, Connaught Place, New Delhi–110 001
G C International Ltd., 3B-57, Blue Moon Estate, Ground Floor, Monginis Lane, Off Andheri Link Road, Andheri (W), Mumbai	Alpha Chemika, Mohid Heights Unit No. 5, 4th Floor, Lokhandwala RTO Road, off Four Bungalows, opp Versova Tel Exchange Andheri (W), Mumbai
Moraya Global Pvt. Ltd. , Plot No. A–42, Street No.2, M.I.D.C., Andheri (East), Mumbai, Maharashtra, Pin–400 093	Deepak Chemicals Group, 2207, Phase-IV, GIDC, Vatva, Ahmedabad–382 245,
Bhagat Impex , C-33 & 34, Sector-VII, Noida–201301 (U.P.)	Laurice labs, 308, Anjali, B Wing, Ambika Nagar Soc, M.G. Rd., Dombivli (West), Pin 421202
N.S. Chemicals, 601-611, Devavrata, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai-400	Nagpur Chemicals, W-36, MICD, HINGNA ROAD, NAGPUR–440 016

Fragrances & Flavours Association of India, Navinchandra Ranchhoddas Shah Hall, 2-B, Court Chambers, 2nd Floor, 35, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400 020	
---	--

- vii. None of the importers, users or association filed importers questionnaire response.
- viii. Post hearing, Fragrances & Flavours Association of India filed a letter making certain submissions, although they did not attend the oral hearing. The submissions made by the said association has been examined and addressed along with other submissions made during the course of the investigation.
- ix. Exporters, producers and other interested parties who have not responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- x. At the application stage, the domestic industry filed the petition by relying upon imports data obtained from International Business Information Service, Mumbai (IBIS). They also furnished imports data from China Customs and by comparing the same with the IBIS data, they claimed that as per China Customs the volume of exports from China during the POI is much more than that reported in the IBIS which is based on Indian Customs data. Subsequently, the domestic industry submitted the transaction wise imports data from China Customs and requested the Authority to rely upon the same for the required analysis as the same reported exports of the product under consideration from China PR during the POI much more than the data from IBIS and DGCI&S.
- xi. The application was filed on the basis of IBIS data and the same was relied upon prima facie for initiating the investigation. Post initiation, transaction-wise imports data was obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S). Comparison of the imports data received from the various sources was made and it is noted that the volume of imports reported in the China Customs data is much more than what is reported in the DGCI&S data. However, the Authority relied upon the DGCI&S data in this finding since high sea sales of the transactions reported in the China Customs data, as provided by the DI, cannot be ruled out.
- xii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry. The NIP has been determined by the Authority in terms of the principles laid down under Annexure III to the Anti-dumping Rules.
- xiii. The period of investigation for the purpose of the present review is April 2013–September 2014. However, injury analysis covered the periods April, 2010–March, 2011, April, 2011–March, 2012, April, 2012–March, 2013 and the POI.
- xiv. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 6th November, 2015. The public hearing was attended by domestic industry only, who presented their views in the oral hearing and were requested to file written submissions of the views expressed orally.
- xv. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry.
- xvi. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been examined and addressed by the Authority, wherever found relevant, in this finding.
- xvii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing

information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- xviii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- xix. ***represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xx. The average exchange rate of 1US\$ = Rs 60.76 prevailing during the POI has been adopted by the Authority in this finding.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

6. The product under consideration in the present investigation is Coumarin of all types (hereinafter referred as subject goods). The product is classified under Chapter 29 (Organic Chemical) of the Customs Tariff Act under Customs Sub-heading No. 2932.21.00. However, customs classification is indicative in nature and not binding on the scope of the investigations. Since the present investigation is for sunset review, the scope of the product under consideration remains the same as that of the original investigation. The product under consideration in the final findings of the original investigations was defined as follows:

“The product under consideration in the present investigation is Coumarin of all types (hereinafter referred as "subject goods"). Coumarin (Chemical Formulae C₉H₆O₂) belongs to the lactone family of chemicals. It is an aroma chemical, which can be in the form of white crystals, flake or powder. It has characteristic odour of newly mown hay and bittersweet somewhat similar to vanilla. Coumarin is used in the preparation of fragrance compounds and those fragrance compounds are used in the production of soaps, detergents, cosmetics, incense sticks, and fine fragrances. It imparts pleasant fragrance and masks unpleasant odors in many other household and industrial products. Coumarin, which was originally a natural product obtained from Tonka beans is now produced synthetically. It can be obtained by two synthetic processes i.e. (i) Starting from phenol to obtain Salicylaldehyde followed by Perkin reaction and (ii) Starting from Ortho-cresol which is also called Raschig method in which Salicylaldehyde is made from Ortho-cresol and then converted into Coumarin. In both the processes Salicylaldehyde and Acetic Anhydride react in the presence of Sodium Acetate in Acetic Acid as catalyst and crude Coumarin is separated from Acetic Acid by distillation. The crude Coumarin is further purified by several distillations and then crystallized in Methanol. The crystallized product is separated by centrifugation and dried. The main physical specification of Coumarin is its purity, for which the melting point is the indicator.”

7. None of the interested parties made any submissions regarding the product under consideration at any stage of the proceedings. This investigation being a sunset review, the Authority considers the product under consideration as defined in the final findings of the original investigations for the present review investigation as well.
8. With regard to like article, Rule 2(d) provides as:—

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

9. The petitioner has claimed that there are no known differences in subject goods produced by the Indian industry and exported from China PR. The product under consideration produced by the Indian industry and imported from subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

10. The Authority notes that none of the interested parties have raised any argument in relation to product under consideration and like article. The Authority, therefore, holds that the subject goods produced by the domestic industry is like article to the subject goods imported from subject country in accordance with the AD rules for the purpose of the present investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

Submissions made by the Exporters/Importers/users/other Interested Parties

11. With regard to scope of the domestic industry and standing, no submissions have been made by the exporters/importers/users/other interested parties.

Submissions made by Domestic Industry

12. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry:
 - i. The petition was filed by Atlas Fine Chemical Pvt. Ltd., the sole producer of the subject goods in India. However, M/s. Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd. has been acquired by its related company M/s. Aims Impex Pvt. Ltd. with effect from 23rd October. All Assets and liabilities of M/s. Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd. have been transferred to Transferee Company i.e. Aims Impex Pvt Ltd.
 - ii. Promoters for both the companies are same before and after amalgamation. As regards the business operations, Atlas was the producer of Coumarin, whereas Aims Impex was the producer of Vanalin prior to amalgamation. After amalgamation, Atlas Fine Chemicals has been merged into Aims Impex. Aims Impex is now the producer of both Coumarin and Vanalin.
 - iii. The management took decision for amalgamation in view of the fact that it would be advantageous to combine the activities and operations in a single company to reap synergetic advantages such as supply chain and logistics alignment, benefit from the increased scale of operations, saving in various fixed cost etc. Consolidation of business will result in savings of cost and improvement in the revenues and margins. Availability of common operating platform will provide an opportunity to leverage combined assets and build a stronger sustainable business.
 - iv. Neither Atlas Fine Chemical Pvt. Ltd. nor Aims Impex Pvt. Ltd. has imported the subject goods during the period of investigation, or, are related to any exporter or producer of the subject goods in China or an importer or user of the product under consideration in India within the meaning of Rule 2(b).
 - v. There is no other known producer of Coumarin in India and hence the production of petitioner constitutes 100% of the Indian production.

Examination by the Authority

13. According to Rule 2 (b), “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.
14. The Authority notes that in the previous investigation the Authority accepted that:

“The Authority holds that the M/s Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd is the sole producer of the like article in India and constitutes ‘domestic industry’ within the meaning of the Rule 2(b) of the AD Rules. The Authority further holds that the application satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules.”
15. The Authority further notes that the petitioner is M/s. Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd. However, post initiation of investigations, the identity of the petitioner has changed. Atlas Fine Chemicals has been merged into its related company, Aims Impex Pvt. Ltd. The Authority examined and found that there is no change in the status of the petitioner even after amalgamation in terms of ownership, assets and liabilities etc. The Authority, therefore, holds

that M/s. Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd., now known as M/s. Aims Impex Pvt. Ltd., is the domestic industry for the product under consideration.

E. Other issues

Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

16. No submissions have been made by the producers/exporters/importers/other interested parties in this regard. However, post oral hearing, the following submissions have been made by Fragrance and Flavours Association of India, who did not attend the oral hearing despite intimation:
 - a. Imposition of anti-dumping duty would increase the cost of production of Perfumery Compound, Cosmetics, Agarbatti (Incense Sticks) etc. Further, increase in cost of production would adversely affect their exports. It would be prudent to create and maintain healthy and competitive environment for our industry to compete successfully in the global markets.
 - b. The proposed structure of Anti-dumping duty is unfairly excessive. It should be just, fair and minimal.
 - c. The proposal of levying Anti-dumping Duty on originating / Imports of Coumarin from China PR., in its present form could encourage the formation of CARTEL. Moreover, the unusual disparity of price between domestic and Chinese products would mean contravention of Monopolies and Restricted Trade Practice.

Submissions made by the Domestic Industry

17. Following are the submissions made by the domestic industry:
 - i. Petitioner has procured IBIS transaction wise data along with China customs data. Petitioner has also procured DGCIS transaction-wise import data. On comparison of DGCIS data with the data received from IBIS and China customs, it is found that the DGCIS is showing import volumes significantly below the volumes reported in China customs. Further, the volumes reported in IBIS are even lower than volumes reported in DGCIS.
 - ii. The import price reported in DGCIS transaction wise data is materially higher than the China customs prices. Further, the price reported in IBIS is significantly higher than DGCIS transaction wise data.
 - iii. It is settled position of the Directorate that the Directorate would consider the data which shows highest volumes. Since the import volumes reported in China Customs are the highest, the Authority should consider China customs data.
 - iv. A comparison of the information as per various sources shows that significant volumes of exports of product under consideration have been made from China to India and at far lower prices than reflected in the Indian Customs.

Year	Volume-MT			Rate/Kg		
	DGCIS (t-t)	IBIS	China Customs	DGCIS (t-t)	IBIS	China Customs
2010-11	182	253	186	428	449	421
2011-12	188	122	166	459	496	452
2012-13	115	144	174	503	497	433
POI	105	55	202	634	730	513
POI (ann)	70	36	134	634	730	513

**China Customs prices are at CIF level.*

- v. In view of the above, the import volume and price for the purpose of dumping and injury margin is required to be determined on the basis of China customs prices.

- vi. An analysis of the volume of exports reported over the years shows that volume of imports in case of subject country has remained significant despite imposition of anti dumping duty. The present trend shows that there are all probabilities that the volume would increase in the event of cessation of anti dumping duty. Considering the level of significant volume of imports at present, there is no reason to believe that the volume will decline in the event of cessation of anti dumping duty.

Volume of Imports (MT)

Particulars	Imports from China PR
2005-06	188
2006-07	194
2007-08	220
2008-09	225
2009-10	433
2010-11	187
2011-12	169
2012-13	176
POI	138

*Based on IBIS up to 2009-10 and China Customs thereafter

Examination by the Authority

18. As regards the submission that imposition of anti-dumping duty would increase the cost of production of Perfumery Compound, Cosmetics, Agarbatti (Incense Sticks) etc and adversely affect their exports, the Authority notes that the objective of anti-dumping measures is to create a level playing field for the domestic industry against the unfair trade practices of dumping. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way; and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
19. As regards the submission that imposition of anti-dumping duty would encourage cartelization and therefore the same should be just, fair and minimal, the Authority notes that the recommendation of continued imposition of duty in the present investigation is on the basis of likelihood analysis. The Authority has examined dumping and injury in the present investigation for POI and post POI and in respect of third country as well. While the investigation shows continued dumping of the subject goods from the subject country during POI despite the anti-dumping duty in force, injury to the domestic industry on account of such dumping is likely to recur in the event of revocation of the anti-dumping duty if the subject goods are imported in to India from the subject country at the prices at which the subject country is exporting the subject goods to the third countries.
20. As already explained in this finding, the Authority relied upon the IBIS data furnished by the applicant domestic industry prima facie for the purpose of initiation of the investigation. Post initiation, request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) to arrange for details of transaction-wise imports of subject goods for the injury period including POI and post-POI and the same was received by the Authority. The volume of imports from China to India during the POI was also checked up from the World Trade Atlas (WTA) data. The details of imports in the various sources of data, as provided by the domestic industry, DGCIS and World Trade Atlas during the POI are as follows:

	Volume-MT				Rate Rs/Kg			
Year	DGCIS	IBIS	China Customs	WTA	DGCIS	IBIS	China Customs	WTA
POI	110	55	207	207	673	730	538	538

21. The Authority noted that there is a wide variation between the imports data from the IBIS, DGCI&S and China Customs. However, the data purportedly from China Customs as furnished by the domestic industry cannot be relied upon since high sea sales cannot be ruled out. The Authority has, therefore, relied upon the imports data obtained from DGCI&S in the present investigation.

F. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

Submissions made by exporters, importers and other interested parties

22. No submissions have been made by the exporters, importers and other interested parties with regard to market economy, normal value, export price and dumping margin.

Submissions made by the domestic industry

23. The submissions made by the domestic industry in this regard are as follows:
- i. China is a non-market economy. No country has granted market economy country status to China after following elaborate evaluation parameters.
 - ii. Normal value in case of China should be determined in accordance with para-7 Annexure-I to the Rules.
 - iii. India and China are the only producers of the product under consideration in the World. There is no other country to constitute a representative third country for consideration of price from a third country to India. Thus, due to unavailability of information, India can be considered an appropriate surrogate country for Chinese producers.

Examination of the Authority

Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR

24. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as non-market economy country in the anti-dumping investigations by other WTO Members. Therefore, in terms of Para 8 (2) of the annexure 1 of AD rules, China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the above presumption by the exporting country or individual Producers/Exporters in terms of the above Rules.
25. As per Paragraph 8 of Annexure I of the Anti-dumping Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:
- a. the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - b. the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - c. such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
 - d. the exchange rate conversions are carried out at the market rate.
26. Paragraph-7 of the Annexure-1 to the Anti-dumping Rules provides as follows:

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated Authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments”

27. According to these Rules, the normal value in China can be determined on any of the following basis:
 - a) On the basis of the price in a market economy third country, or
 - b) The constructed value in a market economy third country, or
 - c) The price from such a third country to other countries, including India.
 - d) If the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.
28. The petitioner has claimed that normal value in China can be determined on the basis of (a) import price from third country into India, (b) selling price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit. Petitioner has further claimed that since these options for determination of normal value are available, the Designated Authority may not kindly consider "any other basis" as "any other basis" option is required to be applied only when other basis listed under the law cannot be applied. However, in the instant case, information on other basis is available and therefore "any other basis" should not be applied.
29. The Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority, none of the producers or exporters from China PR have filed Exporter's Questionnaire Response or Market Economy Treatment (MET) Response or filed any submissions. The Authority notes that there is no other known producer in any third country to select an appropriate market economy third country for the purpose of determination of normal value in case of China PR. Moreover no interested party has made any submission in this regard and made available the required information. Under the circumstances, the Authority is not in a position to apply Para 8 of Annexure 1 to the Rules and therefore proceeds to construct the normal value based on any other reasonable basis in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.
30. The Authority notes that in the current circumstances, due to unavailability of information, India can be considered as an appropriate surrogate country for Chinese producers which would result in access to accurate and adequate information. India has been considered as an appropriate surrogate by other Investigating Authorities too. Under such circumstances the Authority proceeds to construct the normal value based on any other reasonable basis in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.
31. In terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules, the Authority has constructed the Normal value for the Chinese producers on the basis of efficient consumption norms and conversion cost of the domestic industry, after including selling, general & administrative costs and reasonable profit margin. The Authority proposes to determine the normal value accordingly as per the table given below.

G. EXPORT PRICE

32. According to Section 9A(1)(b) of the Customs Tariff Act, 1975, 'export price' in relation to an article means:

“export price”, in relation to an article, means the price of the article exported from the exporting country or territory and in cases where there is not export price or where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported articles are first resold to an independent buyer or if the article is not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

33. The Authority proposes to determine export price by considering WTA data for the POI. Since the export price as per WTA data is FOB price, the Authority has considered the general adjustments for the expenses, which may have been incurred by the exporters for exporting the PUC to India, to arrive at the net export price. The Authority has made appropriate adjustments for commission, bank charges, port expenses, inland freight charges and VAT difference.

H. DUMPING MARGIN

34. Considering the proposed normal value and export price as determined above, the proposed dumping margin determined by the Authority for the POI is as below:

Particulars	Unit	POI
Constructed Normal Value	US \$/Kg	***
Net Export Price	US \$/Kg	***
Dumping Margin	US \$/Kg	***
Dumping Margin	%	***
Dumping Margin	Range %	0-10

35. The Authority notes that the proposed dumping margin during the POI, although not substantial, is positive, thereby implying that the anti-dumping duty in force on the imports of the product under consideration, originating in or exported from China, has not been effective and the dumping continued despite the anti-dumping duty in force.
36. The Authority has examined the data pertaining to the post POI as well and determined the likely dumping margin during post POI period as below:

Particulars	Unit	Post-POI
Constructed Normal Value	US \$/Kg	***
Net Export Price	US \$/Kg	***
Dumping Margin	US \$/Kg	***
Dumping Margin	%	***
Dumping Margin	Range %	5-15

37. The Authority notes that the likely dumping margin during the post POI is not only positive but also substantial.
38. The Authority also examined the impact of Chinese exports to the third countries during the POI from the World Trade Atlas data and determined the likely dumping margin from the angle of third country data as below:

Particulars	Unit	Third Country
Constructed Normal Value	US \$/Kg	***
Net Export Price	US \$/Kg	***
Dumping Margin	US \$/Kg	***
Dumping Margin	%	***
Dumping Margin	Range %	15-25

39. The Authority notes that the likely dumping margin determined on the basis of third country data is also substantial. From the World Trade Atlas data, the Authority notes that the average net export price of Chinese exports of product under consideration to the world over is US\$ ***/Kg. Considering the proposed CNV determined for China during the POI as US\$***/Kg, the dumping is not only positive but also substantial. This implies that in the event of revocation of the anti-dumping duty, if China exports the product under consideration to India at the same average price at which China is exporting to the rest of the world market, the same is likely to result in intensified and significant dumping. The likelihood of dumping in the event of revocation of the anti-dumping duty becomes more imminent considering the fact that the domestic industry in the present investigation is the sole producer of product under consideration in the country and China enjoys literal monopoly in the world market due to its huge production capacity and penchant for exports. It may not be incorrect to say that in the event of revocation of the anti-dumping duty, the sole domestic industry in India may have to close down in the face of recurrence of intense Chinese dumping.

I. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

Submissions made by the exporters, importers and other interested parties

40. No submissions have been made by the exporters, importers and other interested parties with regard to methodology for injury determination and examination of injury and causal link.

Submissions made by the domestic industry

41. Following are the submissions made by the domestic industry in this regard:

- i. Imports from China have continued in spite of anti dumping duty being in force.
- ii. Performance of the domestic industry has been stable or improved in respect of various economic parameters. However, the volume of import has remained significant.
- iii. Imports would undercut the domestic price in the absence of anti dumping duty.
- iv. Cessation of anti dumping duty shall have significant adverse price effect on the prices of the domestic industry in the market as is evident from the fact that excessive exports from China PR have led to the closure of domestic production in EU and USA.
- v. Imports made into the domestic market have been made at dumped prices despite imposition of anti-dumping duty. There is huge probability of massive imports of dumped subject goods in the event of cessation of anti dumping duty.
- vi. Producers in the subject country have significant capacity which establishes that in the event of cessation of duties, exports to India will intensify.
- vii. The exporters from subject country are exporting the product under consideration to third countries at dumped prices.
- viii. The dumping margin in the current POI is positive and significant.
- ix. The import prices are materially below selling price of the domestic industry and also the benchmark anti dumping duty. The consumers would therefore switch to imported product in the event of cessation of anti-dumping duty which will lead to significant increase in imports of the product.

- x. Significant volumes of the dumped imports are at prices below cost of sales of the domestic industry and therefore are likely to lead to price suppression and depression in the market. In case of cessation of anti-dumping duty, the domestic industry shall have to reduce their selling price further to compete with dumped imports, driving it even below the cost of sales; leading to severe price injury.
- xi. In a situation where the import price in different transactions varies so significantly as is the situation in the present case, the domestic industry is required to benchmark itself to the lowest import price. The consumers would not consider the average prices reported in this period. The consumers would consider the lowest prices reported in this period and would require the domestic industry to match those prices. Thus, the fact that significant imports are at higher prices in this period is of advantage to the domestic industry. What is relevant to the domestic industry is the price up to which the Chinese producers can reduce the prices and sell the product.

Examination by Authority

- 42. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
- 43. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the rules supra.
- 44. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Further, since anti-dumping duties are in force on imports of the product under consideration, the Authority considers whether the existing anti-dumping duties on the imports of subject goods from the subject countries are required to be considered while examining injury to the domestic industry. The Authority has examined whether the existing anti-dumping measure is sufficient or not to counteract the dumping which is causing injury.
- 45. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
- 46. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd. (presently known as Aims Impex Pvt. Ltd.), constituting domestic industry under the Rules. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:-

Volume Effect

Demand and Market Share

- 47. Demand or apparent consumption of the product in India, as given in table below, is the sum of domestic sales and imports from all sources.

Demand into India	Units	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	Apr'13-Sep'14 (POI)	Post POI Annualised	Post POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***	***	***	***
	Trend	100	107	181	265	265	239	239
Imports- Subject Country	MT	283.13	191.04	128.79	57.48	106.95	77.20	38.60
Imports-Other Countries	MT	257.00	5.40	0.01	0.01	2.90	3.83	1.92
Total Demand	MT	***	***	***	***	***	***	***
	Trend	100	51	57	65	65	63	63
Market Share								
Domestic Industry	%	***	***	***	***	***	***	***
Range	%	15-25	40-50	60-70	80-90	80-90	75-85	75-85
Other Indian Producers	%	***	***	***	***	***	***	***
Subject Country	%	41.21	54.08	32.62	12.86	15.40	17.85	17.85
Other Countries	%	37.41	1.53	0.00	0.00	0.42	0.89	0.89

48. The Authority notes that the demand for the subject goods has increased consistently throughout the injury period. Similarly, the sales and market share of the domestic industry have increased.

Import Volume and share of Subject country

49. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Information in the table below shows that imports from China have substantially declined over the injury period, but still continues to at dumped prices and showing upward trend during post POI.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	Apr'13-Sep'14 (POI)	Post POI Annualised	Post POI
Imports- China PR	MT	283.13	191.04	128.79	57.48	106.95	77.20	38.60
Imports- Other countries	MT	257.00	5.40	0.01	0.01	2.90	3.83	1.92
Total Imports	MT	540.13	196.44	128.80	57.49	109.84	81.03	40.52
Market Share in relation to								
Total Imports	%	78.62	55.61	32.62	12.86	15.82	18.73	18.73
Petitioners' Production	%	***	***	***	***	***	***	***
Range	%	15-25	40-50	60-70	80-90	80-90	75-85	75-85

Price Effect

50. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price under cutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

Price Undercutting and Underselling

51. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority considered whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of like article/product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The Authority also assessed the underselling effect of the import prices on the domestic industry as below:

Particulars	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	Apr'13-Sep'14 (POI)	Post POI
Non Injurious Price	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>		<i>100.00</i>	<i>103.15</i>	<i>104.36</i>	<i>113.26</i>	<i>113.26</i>	<i>115.65</i>
Landed value of imports	Rs/MT	345	505	602	689	689	629
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	(***)	(***)	***
Price undercutting %	%	***	***	***	(***)	(***)	***
Price undercutting Range	%	70-80	20-30	0-10	(0-10)	(0-10)	5.15
Price underselling	Rs/MT	***	***	***	(***)	(***)	(***)
Price underselling %	%	***	***	***	(***)	(***)	(***)
Price underselling range	%	-	-	-	(5-15)	(5-15)	(0-10)

The Authority notes that the price undercutting is negative during POI but positive during post POI. But, underselling is negative both during POI and post POI.

Price Suppression / Depression

52. The Authority notes that a comparison has been made between the cost of production and net selling price of the domestic industry and landed value of imports. Imports are not causing price suppression or depression effect either in POI or post POI.

Particulars	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	Apr'13-Sep'14 (POI)	Post POI
Cost of sales	Rs./Kg	***	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100.00</i>	<i>109.36</i>	<i>105.25</i>	<i>106.05</i>	<i>106.05</i>	<i>107.10</i>
Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100.00</i>	<i>103.15</i>	<i>104.36</i>	<i>113.26</i>	<i>113.26</i>	<i>115.65</i>
Landed Value	Rs./Kg	345	505	602	689	689	629
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>146</i>	<i>174</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>182</i>

J. EXAMINATION OF ECONOMIC PARAMETERS RELATING TO DOMESTIC INDUSTRY

53. According to Annexure II to the AD Rules, the determination of injury shall involve an object examination of the consequent impact of the imports of subject goods on domestic producers of the subject goods. The relevant extract of the said Rule is reproduced herein below –

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”

54. Accordingly, various economic parameters of the Domestic Industry are analyzed herein below.

Sales, Capacity, Production and Capacity Utilization

55. Information regarding sales, capacity, production, and capacity utilization of the Domestic Industry is as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	Apr'13-Sep'14 (POI)	Post POI Annualised	Post POI
Capacity	MT	***	***	***	***	***	***	***
	Trend	100	100	100	107	107	120	120
Production	MT	***	***	***	***	***	***	***
	Trend	100	100	141	253	253	216	216
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***	***	***
Range	%	25-35	25-35	40-50	70-80	70-80	50-60	50-60
Domestic sales	MT	147	157	266	390	584	352	176
	Trend	100	107	181	265	265	239	239
Demand	MT	***	***	***	***	***	***	***
	Trend	100	51	57	65	65	63	63

56. The Authority notes that Production, sales and capacity utilization have shown improvement over the injury period. The domestic industry has increased their capacity as well during POI.

Market Share

57. The Authority notes that the market share of the domestic industry has increased over the injury period and the market share of the subject country has declined. However, the market share of subject country is showing upward trend during the post POI.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI
Domestic industry	%	***	***	***	***	***
China	%	41.21	54.08	32.62	15.07	17.85
Other Countries	%	37.41	1.53	0	0.76	0.89

Profit/Loss, Cash Flow, Return on Capital Employed

58. Information relating to profits, return on investment and cash flow is given in the table below:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	Apr'13-Sep'14 (POI)	Post POI Annualised	Post POI
Per unit profit/loss	Rs. /Kg	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	41	95	185	185	201	201
Profit/loss on domestic sales	Rs. Lakh	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	44	173	490	490	480	480
Profit before interest & tax	Rs. Lakh	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	44	173	540	540	538	538
Cash Profit	Rs. Lakh	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	59	183	469	469	476	476
Return on Investments	%	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	30	95	221	221	216	216

59. The Authority notes from the table above that the selling price of the domestic industry increased over the injury period. Resultantly, profits, cash profits and return on investment have shown improvement over the injury period. The Authority notes that the domestic industry could increase its selling price and earn profits as a result of imposition of anti dumping duty.

Inventories

60. The Authority notes that the average inventory level of the domestic industry has declined in the POI as a result of increase in the sales volume.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	Apr'13-Sep'14 (POI)	Post POI
Average Stock	MT	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	110	103	56	30

Employment, wages and productivity

61. The Authority notes that the employment has declined, but wages have gone up. Productivity of the domestic industry has also shown improvement.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	Apr'13-Sep'14 (POI)	Post POI Annualised	Post POI
Employment	Nos	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	101	86	91	91	91	91
Wages	Rs. Lakh	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	87	111	137	137	174	174
Productivity per employee	MT/No s.	***	***	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	98	163	278	278	238	238
Productivity per day	MT/day	***	***	***	***	***	***	***
	Index	100	100	141	254	254	217	217

Factors affecting domestic prices

62. The Authority notes that during POI, the landed value of imports is marginally higher than the domestic industry's selling price, thereby resulting in negative price undercutting. However, during post POI, the price undercutting has become positive and substantial. China being sole source of imports and the product under consideration having no substitute, in the event of revocation of the duty, the domestic industry's prices will be severely undercut by the Chinese dumped prices.

Magnitude of dumping

63. The dumping margin is positive during POI, thereby implying that it is a case of continued dumping despite the imposition of anti-dumping duty.

Growth

64. The Authority notes that during POI the performance of the domestic industry in terms of both volume and price parameters shows an improvement as a result of imposition of anti dumping duty on dumped imports. However, during post POI, the overall performance of the domestic industry has declined thereby meaning that in the event of revocation of the anti-dumping duty, the growth of the domestic industry will deteriorate.

Particulars	Units	2010-11	2011-12	2012-13	POI	Post POI
Production	%	-	(0.46)	41.09	80.14	(14.47)
Domestic Sales	%	-	6.76	69.61	46.47	(9.78)
Cost of sales	%	-	9.36	(3.75)	0.76	0.99
Selling Price	%	-	3.15	1.17	8.52	2.11
Profitability	%	-	(55.77)	290.89	183.70	(2.07)
ROI	%	-	(69.56)	212.11	132.51	(2.07)

Ability to raise Capital Investment

65. The Authority notes that the domestic industry has added capacity in the POI.

K. Causal Link

66. The Authority examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

- Volume and value of imports not sold at dumping prices:**—The Authority notes that the imports from other sources are very negligible to have any impact on the Indian market.
- Contraction in demand:**—The Authority notes that there is no contraction in the demand during injury period. Demand for the product has increased over the injury period. The Authority further notes that the domestic industry has expanded its capacity over the injury period.
- Changes in the patterns of consumption:**—The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change.
- Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:**—The Authority notes that the subject goods are freely importable. The domestic industry is the sole producer of the subject goods and accounts for significant domestic production and sales.
- Developments in technology:**—The Authority notes that none of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.
- Export performance:**—The Domestic Industry has exported the product under consideration in the injury period. The export performance of the domestic industry is not relevant since

price and profitability in the domestic and export market has been segregated by the Authority for the purpose of assessing injury to the domestic industry.

L. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

Submissions by the Domestic Industry

67. The domestic industry submitted as under in support of its claim of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- i. Significant dumping margin during POI establishes that the dumping is likely to continue and intensify in the event of cessation of present anti dumping duty.
- ii. The imports from the subject country has remained significant even in the presence of anti dumping duty, thereby showing that the imports would increase in the event of withdrawal of anti dumping duty.
- iii. Producers in the subject country maintain huge capacities to produce coumarin. In case of cessation of anti dumping duty, the volume of imports is bound to increase further.
- iv. The subject foreign producers are holding huge surplus production capacities, evidence of which is evident from the above mentioned investigation. Record evidence clearly shows that there exists excess capacity with the foreign producers of the subject country as:

“The industry producing Coumarin in China during the original investigation was believed to consist of 3 large producers and 10 smaller firms. According to the petition, the three large producers (Tianjin Number 1, Changzhou Number 2 Plant, and Shanghai Perfumery) had a combined annual capacity of 3.1 million pounds and current annual production of approximately 1.9 million pounds. The 10 smaller producers of the subject product were estimated to have a collective capacity of approximately 700,000 pounds and production of approximately 500,000 pounds. The Chinese coumarin-producing industry, therefore, was estimated to have a total capacity of approximately 3.7 million pounds, 52 production of 2.4 million pounds, capacity utilization of 65 percent, and unused capacity amounting to approximately 1.3 million pounds.”

- v. The exporters from the subject country have very high export orientation worldwide. Hence, the dumping and injury is likely to recur at aggravated level in case the existing anti-dumping duties cease.
- vi. The landed value of imports would undercut the prices of the domestic industry in the absence of anti dumping duty. Therefore, cessation of anti dumping duty is likely to cause significant adverse volume & price effect on the domestic industry.
- vii. Dumping of the product under consideration from the subject country has lead to closure of the domestic production in the European Union and the United States of America.
- viii. The present situation is clearly suggestive that the dumping would intensify in the event of cessation of anti-dumping duty. The petitioner submits that the level of dumping margin during in POI is not only more than de-minimis but also significant. The circumstances, which were prevalent at the time of earlier investigations, are very much in existence even in the present period. It can be concluded from the above determinations that excessive exports from China PR have led to the closure of domestic production in EU and USA.

Examination by the Authority

68. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires examination whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.
69. The Authority notes that in the present investigation, despite the anti-dumping duty in force, dumping has continued. On the basis of post POI and third country data analysis, the Authority notes that the same is likely to be intensified in the event of revocation of the duty. Moreover, as submitted by the domestic industry, China holds huge capacity for the PUC with tremendous export orientation. If the duty is revoked, the sole domestic industry in India may get vanquished with recurrence of intensified dumping from China PR.

70. The above position is further corroborated by the following analysis:

Particulars	Unit	As per World Trade Atlas Data
Total Volume of Exports to third countries	MT	5143
Volume of Exports at Dumped Prices (when compared with CNV)	MT	4872
Volume of Exports at Injurious Prices (Compared with NIP of DI)	MT	4725
Share of Dumped Exports	%	94.73
Share of Injurious Exports	%	91.87

The Authority notes that 95% of Chinese exports to the world market is at dumped prices, with 92% exports having injurious effect. Therefore, in the event of revocation of the duty by India, the Chinese exports may throw the sole domestic industry out of market.

M. Magnitude of Injury and Injury Margin

71. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during POI. The injury margin proposed to be determined for the subject country, during POI, is as follows:

Injury margin-POI

Particulars	POI
	US\$/Kg
Non-injurious Price	***
Landed Value	11.35
Injury Margin	(***)
Injury Margin (%)	(***)
Injury Margin (%) range	(5-15)

72. The Authority notes that the injury margin during the POI is negative; thereby implying that during the POI the price at which the imports have come from China has no injurious effect on the domestic industry.

73. The Authority further examined the injurious effect of the Chinese imports during the post POI period and determined the likely injury margin as below:

Injury margin-post POI

Particulars	Post POI
	US\$/Kg
Non-injurious Price	***
Landed Value	10.05
Injury Margin	(***)
Injury Margin (%)	(***)
Injury Margin (%) range	(0-10)

The Authority notes that the likely injury margin during the post POI is also negative.

74. Since the injury margin during POI as well as post POI has been negative, the Authority assessed the likely injury margin on the basis of the average Chinese export price to the third countries based on the World Trade Atlas Data as below:

Injury margin—Third Country Price during POI

Particulars	Third Country
	US\$/Kg
Non-injurious Price	***
Landed Value	9.86
Injury Margin	***
Injury Margin (%)	***
Injury Margin (%) range	0-10

75. From the aforesaid information, the Authority notes that in the event of revocation of the anti-dumping duty, the domestic industry is likely to get injured if the subject country exports the subject goods at the same average price at which they are exporting to the third countries.

F. Post Disclosure Comments

76. Post disclosure, the following comments have been made by the domestic industry:

- i. Dumping from China has continued despite anti dumping duty being in force.
- ii. 95% of Chinese exports to the world market are at dumped prices, with 92% exports having injurious effect as is evident from the data showing exports from China to world market.
- iii. Cessation of anti dumping duty would lead to intensified dumping resulting in injury to the domestic industry.
- iv. Dumping of the product under consideration from the subject country has lead to closure of the domestic production in the European Union and the United States of America.
- v. The survival of the sole Indian producer would be put at stake in such a global scenario.
- vi. Import prices reported in Indian customs data is the price realigned with the benchmark anti dumping duty and is not reflective of the actual price of imports.
- vii. In view of continued dumped imports causing likelihood of intensified dumping and subsequent injury to the domestic industry, anti dumping duty is required to be extended further for a period of five years in the existing quantum and form expressed in US\$ terms.

77. Post disclosure, Fragrances and Flavours Association of India stated that they could not attend the oral hearing held by the Authority on 6th November, 2016 due to postponement of the hearing. However, the Authority notes that vide letter dated 21st October, 2015, the interested parties including Fragrances and Flavours Association of India were informed that the oral hearing has been scheduled on 6th November, 2015 at 3.00 PM in the DGAD Conference Room, Jeevan Tara Building, 4th Floor, 5, Parliament Street, New Delhi-110001. The interested parties were requested to intimate their interest in the hearing and name and address of the persons who are likely to attend the hearing. The oral hearing was held by the Authority as per the scheduled date, time and venue. While the representatives of domestic industry attended the oral hearing and made submissions, the representative of Fragrances and Flavours Association of India did not attend the oral hearing. Therefore, the Contention that they could not attend the oral hearing due to postponement is baseless.

N. Conclusions:

78. After examining the submissions made by the interested parties including the post disclosure comments and facts available on record, the Authority concludes as below:
- i. The product under consideration has been exported to India from the subject country below normal value during the POI despite the anti-dumping duty in force.
 - ii. During the POI and post POI, although dumping has continued and dumping margin determined by the Authority is positive, it has not caused injury to the domestic industry.
 - iii. Chinese prices to third countries are dumped prices and if the product under consideration is imported in to India at the said prices, in the event of revocation of the anti-dumping duty, such imports are likely to cause injury to the domestic industry.

O. Indian industry's interest & other issues

79. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way; and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
80. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

P. Recommendations

81. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the Act and the Rules and having established positive dumping during POI and post POI and likelihood of injury when compared to the prices of Chinese exports to third countries in the event of revocation of the anti-dumping duty, the Authority is of the view that continued imposition of the anti-dumping duty is required to offset the likelihood of dumping and 'injury' in the instant matter. In view of the finding that the expiry of the anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority considers it necessary to recommend continued imposition of definitive anti-dumping duties.
82. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends continued imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Considering that the anti-dumping duty in the original investigation was imposed on reference price basis, the Authority recommends continuation of definitive anti-dumping duty, on all imports of subject goods, originating in or exported from the subject country, as the difference between the landed value of imports and the reference price, in the same form and manner as imposed earlier vide Notification No. 12/2012-Customs (ADD) dated 8th February, 2012 and Notification No. 8/2015-Customs (ADD) dated 7th April, 2015. Accordingly, the anti-dumping duty equal to the difference between the amount indicated in Col 8 of the table below and the landed value is recommended to be imposed on all imports of subject goods, originating in or exported from China PR.

Duty Table

Sl. No.	Heading/ Subheading	Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty of Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2932.21	Coumarin of all types	China PR	China PR	Any	Any	14.02	KG	US\$
3	2932.21	Coumarin of all types	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	14.02	KG	US\$
4	2932.21	Coumarin of all types	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	14.02	KG	US\$

83. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

Q. Further Procedures

84. An appeal against this order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

A. K. BHALLA, Designated Authority